

[2023] 6 एस. सी. आर 930

साबीर अली खान

वी.

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य

(सिविल अपील सं। 7086-7087 2009)

13 अप्रैल, 2023

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश राय, जे. जे.]

वक्फ अधिनियम, 1995:

शिया मुसलमान पक्षकारों की वक्फ संपत्तियाँ

लाभार्थी और उनके अधिकार-प्रतिकूल कब्जे द्वारा शीर्षक को परिपूर्ण करने वाले लाभार्थी-आयोजित करने की अनुमति: वक्फ का लाभार्थी, जो न तो न्यासी है और न ही वक्फ संपत्ति का सह-मालिक है, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, भले ही वह वक्फ की संपत्ति हो-प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व के अधिग्रहण का दावा करने वाले वक्फ के लाभार्थी के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है-वक्फ के लाभार्थी को वक्फ के लिए अजनबी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है-इसमें कोई संदेह नहीं है, एक लाभार्थी को अपने पद पर मुतवल्ली के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जो वक्फ का प्रबंधक है-वक्फ की संपत्ति, कानून में सर्वशक्तिमान में निहित है-एस के उद्देश्यों के लिए। 10 सीमा अधिनियम के अनुसार, उसे एक न्यासी के रूप में माना जाता है-लाभार्थी प्राप्त करने का हकदार होगा

वक्फ विलेख के संदर्भ में लाभ-प्रतिकूल कब्जे के मामले में, क्योंकि एक आवश्यकता यह है कि कब्जा वास्तविक मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण होना चाहिए और चूंकि वास्तविक मालिक सर्वशक्तिमान है, इसलिए आवश्यकता यह होगी कि ऐसे व्यक्ति को भगवान की उपाधि के विपरीत धारण करने के लिए आवश्यक शत्रुता होनी चाहिए-एक सह-मालिक के मामले में जबकि केवल अपने आप में स्वामित्व का दावा करना मुश्किल से पर्याप्त हो सकता है क्योंकि सह-मालिक के कब्जे को सभी सह-मालिकों की ओर से कब्जा माना जाता है, निष्कासन का मामला सफलतापूर्वक स्थापित होने से अधिकार प्राप्त होगा।

सफल होने के लिए सह-मालिक-वक्फ के लाभार्थी को वक्फ विलेख के संदर्भ में अधिकार दिए जाते हैं-सुरक्षा के लिए कोई कर्तव्य नहीं लिया जाता है।

दूसरे का हित। एसएस। 52 (2) और 107-धाराओं के उल्लंघन में हस्तांतरित वक्फ संपत्ति की वसूली। 51 - एक शिया मुसलमान द्वारा बनाया गया वक्फ

वर्ष 1934 में विलेख-मूल वाकीफ के तीन बेटे थे-सबसे बड़ा बेटा क्यू. ए. अपने पिता की मृत्यु पर मुतवल्ली बन गया-हालाँकि, उसका छोटा बेटा।

भाइयों ने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम बदलकर भूमिदार बना लिया

उक्त संपत्ति के लिए-सबसे बड़े बेटे द्वारा दायर मुकदमा जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि यह एक वक्फ संपत्ति थी और अपने दो भाइयों के नामों को हटाने से राहत मांगी गई थी-मुकदमा लंबित रहने के दौरान, क्यू. ए. के एक भाई ने अपना एक-तिहाई हिस्सा अपने भतीजे को बेच दिया, जिसे पहली बिक्री के रूप में संदर्भित किया गया था-हालांकि कहा गया मुकदमा वादी के पक्ष में घोषित किया गया था, लेकिन समेकन कार्यवाही को देखते हुए इसे समाप्त कर दिया गया-पहली बिक्री थी

हस्तांतरणकर्ता कि क्यू. ए. का बेटा मुतवली बन गया-लिखित याचिका वापस लिया गया-क्यू. ए. के दूसरे बेटे द्वारा यू. पी. शिया वक्फ बोर्ड के समक्ष दायर शिकायत में उनके द्वारा वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण को चुनौती दी गई

पिता और चाचा, साथ ही समझौता-वक्फ बोर्ड के नियंत्रक एस का आह्वान करके। 52 (1) कलेक्टर को अनधिकृत कब्जाधारियों, क्यू. ए. के भतीजे-प्रथम उत्तरदाताओं से विवादित भूमि का कब्जा वसूल करने और वितरित करने का निर्देश दिया-कलेक्टर ने उत्तरदाताओं को 30 दिनों के भीतर बोर्ड को संपत्ति का कब्जा देने का निर्देश दिया पहले उत्तरदाताओं ने इसे चुनौती दी और अपीलों को ए. डी. जे. द्वारा अनुमति दी गई-हालांकि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि ए. डी. जे. के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है-अपील में, वक्फ न्यायाधिकरण ने कहा कि उत्तरदाताओं ने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार हासिल कर लिया था और कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया-कहा

उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया-हालाँकि, पुनरीक्षण याचिकाएँ खारिज कर दी गई अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: वक्फ के लाभार्थी, न तो ट्रस्टी होने के नाते और न ही वक्फ संपत्ति के सह-मालिक होने के नाते, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त किया, भले ही वह वक्फ की संपत्ति हो-उच्च न्यायालय

यह सही माना गया कि पिता ने एक शिया मुसलमान की आवश्यकता के अनुसार एक वैध और प्रभावी वक्फ बनाया और उनकी मृत्यु के बाद, उनके सबसे बड़े बेटे ने मुतवली के रूप में पदभार संभाला। 49 ए और 49 बी को 1971 के अधिनियम 28 द्वारा जोड़ा गया और दूसरी बिक्री 1974 में हुई, जो एस. एस. को शामिल करने के बाद हुई। 49 1960 के अधिनियम में क और 49 ख, इस प्रकार, अधिकार की वसूली के लिए कार्रवाई करने की शक्ति बोर्ड के पास निहित है। 49 बी-इस प्रकार, सबसे बड़े बेटे द्वारा अपने भतीजे के पक्ष में वर्ष 1974 का बिक्री विलेख, जो बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना बिक्री के खिलाफ निषेध के दायरे में था, अवैध था-ताकि एक मुकदमा यू/आर्ट के तहत आ सके। 96 , एक प्रबंधक द्वारा एक स्थानांतरण होना चाहिए जिसमें एक वक्फ-कला का मुतवल्ली शामिल होगा। 96 [2023] 6 एस. सी. आर. के रूप में लागू नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह एक अमान्य बिक्री का मामला है न कि अमान्य बिक्री-उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960-का। 49 ए, बी।

एस. 107 - वक्फ संपत्तियों की वसूली-वर्ष 1960 में हुई पहली बिक्री के संबंध में Art.96 और 65 की प्रयोज्यता।

और दूसरी बिक्री वर्ष 1974 में, जब वक्फ अधिनियम 01.01.1996-स्टेट-लिमिटेशन एक्ट, 1963-आर्ट्स पर लागू हुआ। 96 और

65 .

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1.1 उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि की है कि प्रतिवादी नं। 1 में

दोनों मामलों ने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह इस आधार पर है कि पहली बिक्री वर्ष 1960 में और दूसरी बिक्री वर्ष 1974 में की गई थी। यह अधिनियम 1.1.1996 से लागू हुआ। यह अवधि दो बिक्री विलेखों की तारीखों से चलने लगी क्योंकि बिक्री शून्य थी। आगे का निष्कर्ष यह है कि सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 96 वर्ष 1960 की पहली बिक्री पर लागू नहीं होता था। उक्त बिक्री ऐसे समय में की गई थी जब सबसे बड़े भाई क्यू. ए. मुतवल्ली थे। बिक्री एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी जो दूसरे शब्दों में नहीं था मुतवल्ली। इसलिए, अनुच्छेद 96 लागू नहीं हुआ। जहाँ तक दूसरी बिक्री का संबंध है, यह क्यू. ए. द्वारा 26.09.1974 पर लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य अपने भतीजे को अपना एक-तिहाई अधिकार देना था, जो दूसरी अपील में पहला प्रतिवादी है। उच्च न्यायालय का आगे तर्क यह है कि दूसरा बिक्री विलेख मुतवल्ली द्वारा निष्पादित किया गया था। इसके बाद न्यायालय ने अनुच्छेद 65 और 96 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का सीमांकन किया। इसके बाद अदालत ने सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 पर भी विचार किया। अदालत ने उचित पाया

व्याख्या यह थी कि अनुच्छेद 96 को कब्जे की वसूली के लिए मुकदमों तक सीमित रखा जाना था जहाँ कब्जे की वसूली का अधिकार था।

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 के तहत पहले से ही नष्ट नहीं हुआ है। अनुच्छेद 96, दूसरे शब्दों में, यह पाया गया कि यह अमान्य स्थानान्तरणों पर लागू होता है। उक्त आधार पर, यह पाते हुए कि दूसरी बिक्री

अमान्य हस्तांतरण का मामला प्रस्तुत किया गया, यह पाया गया कि अनुच्छेद 96

अपीलार्थी की सहायता नहीं की। यह भी पाया गया कि वक्फ के लाभार्थी द्वारा उपाधि को प्रतिकूल रूप से पूर्ण करने में कोई बाधा नहीं है अधिकार। इस तरह की बाधा, निस्संदेह, एक मुतवल्ली, एक ट्रस्टी या एक सह-मालिक के मामले में मौजूद थी। उपरोक्त में से कोई भी लाभार्थी नहीं था। इस प्रकार, इस आधार पर आगे बढ़ना कि प्रथम प्रतिवादी साबीर अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और

अन्य

बिक्री की तारीख से चलना शुरू हो गया। इसका मतलब यह था कि जब अधिनियम का जन्म 01.01.1996 पर हुआ था, तो शीर्षक प्रतिकूल कब्जे द्वारा पहले प्रतिवादी के पास निहित था। यह आगे पाया गया है कि खंड 107 जिस अधिनियम के तहत सीमा अधिनियम अधिनियम पर लागू नहीं था, वह अपीलार्थी के मामले को बचा नहीं सका। [पैरा 16] [958 जी-एच; 959-ए-ई]

1.2 . जहां तक पहली बिक्री का संबंध है, बिक्री मुतवल्ली या वक्फ के प्रबंधक द्वारा प्रभावित नहीं की गई थी। यह है बिक्री

मुतवल्ली के भाई से प्रभावित था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि अनुच्छेद 96 अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आएगा। [पैरा 20] [961-सी-डी]

1.3 . जहाँ तक दूसरी बिक्री का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे बिक्री विलेख 26.09.1974 द्वारा मुतवल्ली द्वारा निष्पादित किया गया था। यह एक

13.02.1974 पर तीन भाइयों के बीच हुए समझौते के बल पर उनके द्वारा निष्पादित बिक्री। समझौते के कारण उप निदेशक (समेकन) द्वारा दिनांकित 12.09.1974 का आदेश पारित किया गया, जिसमें दिनांकित 20.09.1969 के आदेश द्वारा संशोधन को खारिज करने के साथ-साथ दिनांकित 02.03.1972 के पहले बहाली आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। यदि उक्त बिक्री वैध पाई जाती है, तो जाहिर है, अपीलार्थी विफल हो जाएगा। यदि दूसरी ओर, बिक्री अमान्य है, तो सवाल यह होगा कि क्या बिक्री की तारीख से 12 साल से आगे शुरू की गई कार्यवाही समय के भीतर होगी। [पैरा 21] [961-डी-एफ]

1.4 . इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वक्फ संपत्ति हो सकती है

प्रतिकूल अधिकार द्वारा अधिकार के अधिग्रहण की विषय वस्तु। कि एक मुतवल्ली हालांकि वक्फ पर अधिकार हासिल नहीं कर सकता है प्रतिकूल अधिकार द्वारा संपत्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 96 लागू नहीं होगा क्योंकि यह एक अमान्य बिक्री का मामला है न कि अमान्य बिक्री का। [पारस 22,23] [961-एच; 961-ए]

1.5 . 1971 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 28 के माध्यम से 1960 के अधिनियम में धारा 49 ए और 49 बी को जोड़ा गया था। अतः विक्रय विलेख दिनांकित किया गया है।

26.09.1974 क्यू. ए. द्वारा अपने भतीजे के पक्ष में, [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बोर्ड, अवैध था। यही कथा है जो इस सवाल को जन्म देती है कि क्या बिक्री अमान्य है क्योंकि यह उल्लंघन में थी। एक सांविधिक अधिदेश, और अन्य संबंधित मुद्दे। [पैरा 35] [973 एफ]

1.6 . अधिनियम की धारा 52, जो वक्फ बोर्ड के नियंत्रक और कलेक्टर द्वारा कार्रवाई का प्रमुख स्रोत है, एक

धारा 51 की अगली कड़ी। 2013 के अधिनियम 27 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 51 (1) (ए), प्रावधानों के अधीन, वक्फ संपत्ति की बिक्री, उपहार, विनिमय या बंधक या हस्तांतरण को शुरू से ही शून्य घोषित करती है। अनुभाग

52 अधिनियम में प्रावधान है कि यदि बोर्ड को कोई जांच करने के बाद, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, संतोष होता है कि धारा 36 के तहत बनाए गए वक्फ रजिस्टर में दर्ज की गई वक्फ की किसी भी अचल संपत्ति को अधिनियम की धारा 51 या 56 का उल्लंघन करते हुए बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना स्थानांतरित कर दिया गया है, तो वह उस स्थान के कलेक्टर को एक अनुरोध भेज सकता है जिसके भीतर संपत्ति स्थित है ताकि वह कब्जा प्राप्त कर सके और उसे वितरित कर सके। कलेक्टर व्यक्ति को निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करने के लिए बाध्य है

आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर बोर्ड को संपत्ति देने का अधिकार। इसी प्रावधान के तहत विवादित आदेश पारित किए गए। [पैरा 36,37] [974-बी; 974 डी-एफ] 1.7 . यह अधिनियम 01.01.1996 पर लागू हुआ। धारा 52 बोर्ड को कलेक्टर को अनुरोध भेजने का अधिकार देती है, यदि -

की पूर्व मंजूरी के बिना संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है

बोर्ड धारा 51 के उल्लंघन में, अन्य बातों के साथ। धारा 51 में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना संपत्ति की कोई भी बिक्री, जो वक्फ संपत्ति है, अमान्य होगी। इस मामले में दोनों बिक्री 01.01.1996 से पहले हुई थी। पहली बिक्री दिनांकित 14.10.1960 है जबकि दूसरी बिक्री दिनांकित 13.09.1974 है। [पैरा 38] [974-एफ-एच]

1.8 . 1960 के अधिनियम की धारा 49 बी अधिनियम की धारा 52 के समान है। दूसरे शब्दों में, इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि 1960 के अधिनियम की धारा 49 ए का उल्लंघन करते हुए कोई हस्तांतरण किया जाता है, तो बोर्ड कब्जे की वसूली के लिए कलेक्टर को अनुरोध भेज सकता है। 1960 के अधिनियम की धारा 49 ए में भी समान शर्तों का प्रावधान किया गया है जैसा कि सबीर अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और

अन्य

अधिनियम की धारा 51 (1) में कि संपत्ति की बिक्री के लिए

वक्फ के लिए बोर्ड की पूर्व मंजूरी आवश्यक थी। जहाँ तक 1971 के अधिनियम 28 द्वारा धारा 49 ए और 49 बी अंतःस्थापित की गई और दूसरी बिक्री 1974 में हुई, जो 1960 के अधिनियम में धारा 49 ए और 49 बी को अंतःस्थापित करने के बाद हुई, इसलिए वास्तव में बोर्ड के पास इन धाराओं की वसूली के लिए कार्रवाई करने की शक्ति निहित है -

धारा 49 बी के तहत कब्जा। अधिनियम की धारा 112 (3) के तहत, यह इस आधार पर आगे बढ़ाया जाता है कि 1960 का अधिनियम कायम रहेगा।

निरस्त कर दिया। हालांकि, परंतुक घोषणा करता है कि निरसन संबंधित कानून के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। इस मामले में संबंधित कानून धारा 49 ए है जिसे धारा 49 बी के साथ पढ़ा जाता है। इसके तहत शक्ति के प्रयोग में की गई कार्रवाई को अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग में की गई कार्रवाई माना जाना चाहिए। अधिनियम के तहत शक्तियों को धारा से प्रवाहित माना जाना चाहिए 52 अधिनियम से। धारा 112 (3) के परंतुक में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान, जो इस मामले में धारा 52 होंगे, को कानून पुस्तिका में माना जाना चाहिए। [पैरा 40] [975-डीएच]

[illegible]

1.10 . मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 की धारा 3 बाध्य करती है

मुतवल्ली सक्षम न्यायालय को कुछ विशिष्टताओं वाला बयान प्रस्तुत करेगा। वक्तव्य की सूचना धारा 4 के तहत प्रकाशित की जानी थी। 1923 के अधिनियम में खातों के लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया और मुतवल्ली द्वारा किए जा सकने वाले खर्च का प्रावधान जोड़ा गया। धारा 10 में दंड का प्रावधान किया गया है। कुछ वक्फों को धारा 12 के तहत इसके दायरे से बाहर रखा गया था। संयुक्त प्रांतों में, जिसका अर्थ था संयुक्त

आगरा और अवध प्रांत, 1936 अधिनियम, अधिनियमित किया गया। [पैरा 45] [977-ई-एफ]

1.11 . इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय एक वक्फ अलाल-अलाद के मामले की सुनवाई कर रहा था। निर्णय को अनिवार्य रूप से देखा जाना चाहिए

विचाराधीन अधिनियम में प्रदत्त 'धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य' की परिभाषा का संदर्भ। [पैरा 49] [980-ए] [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चाहे वह 1936 के अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया हो या बनाया गया हो, इसे पंजीकृत किया जाएगा। इस आधार पर कार्यवाही करते हुए कि दिनांकित वक्फ 16.07.1934 वक्फ-अलाल-औलाद था और जो, धारा 2 (2) (i) के संदर्भ में, 1936 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं था, यह धारा 38 (1) को देखते हुए अनिवार्य रूप से पंजीकृत था। कोई भी वक्फ जो 1936 के अधिनियम के तहत पंजीकृत है, उसे भी माना जाएगा 1960 के अधिनियम के तहत पंजीकृत। अर्थात्, यद्यपि 1936 का अधिनियम कुछ वक्फों पर लागू नहीं होता था, लेकिन जब धारा 38 के तहत पंजीकरण की बात आती है, तो प्रत्येक वक्फ के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य था (i) चाहे वह अधिनियम के अधीन हो और ii) चाहे वह अधिनियम से पहले बनाया गया हो या नहीं। इस प्रकार, वक्फ का पंजीकरण दिनांक 16.07.1934, था

वास्तव में 1936 के अधिनियम की धारा 38 के तहत अनिवार्य है। [पैरा 50] [980 बी-ई]
1.13 . यह पाया गया कि शिया कानून और समेकन प्राधिकरणों के दृष्टिकोण से भी एक वैध वक्फ था

यह पाया गया कि तब तक एक वक्फ था जब तक कि उप निदेशक, समेकन ने केवल भाइयों के बीच समझौते के आधार पर मामले पर पुनर्विचार नहीं किया, वक्फ की शर्तों में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित करने पर विचार किया गया था। इस संबंध में, विलेख में शर्त है कि रुपये की राशि 500 / - मुअज़्ज़िन जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों पर खर्च किया जाएगा और मस्जिद और इमामबाड़े में रोशनी की जाएगी, मोहर्रम के पवित्र महीने का मजलिस अशरा मनाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अवशिष्ट खंड है, जिससे पता चलता है कि वाकीफ ने प्रावधान किया है कि यदि वंशजों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो संपन्न संपत्ति से होने वाली आय का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा। [पैरा 51] [980-ई]

एच; 981-ए] 1.14 . आय की सीमा, जो इस उद्देश्य के लिए अलग की जाती है, चाहे वह धार्मिक हो, पवित्र हो या धर्मार्थ, तथ्यों में, पूरी संपत्ति के समर्पण से अलग नहीं हो सकती है।

[पैरा 53] साबीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और

अन्य

1.15 . यह तथ्य कि वक्फ की संपत्ति से इस तरह से निपटा गया है, जो अवैध है, या इस पर सवाल नहीं उठाया गया था,

1.17 . वक्फ के लाभार्थी को वक्फ के लिए अजनबी नहीं बताया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक लाभार्थी को उसकी स्थिति में मुतवल्ली के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुतवल्ली एक प्रबंधक है वक्फ। वक्फ की संपत्ति, कानून में, सर्वशक्तिमान में निहित है। मुतवल्ली केवल प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। के उद्देश्यों के लिए

सीमा अधिनियम की धारा 10, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे न्यासी के रूप में माना जाता है। प्रतिकूल अधिकार की याचिका के लिए निस्संदेह आवश्यकता होती है

अपेक्षित इरादा, अर्थात् , संभव है। यह आवश्यक अवधि के लिए वास्तविक कब्जे के अलावा है। एक लाभार्थी वक्फ विलेख के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रतिकूल अधिकार के मामले में, चूंकि एक आवश्यकता यह है कि अधिकार वास्तविक मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण होना चाहिए और चूंकि वास्तविक मालिक सर्वशक्तिमान है, इसलिए आवश्यकता यह होगी कि ऐसे व्यक्ति को भगवान की उपाधि के विपरीत धारण करने के लिए आवश्यक शत्रुता होनी चाहिए। जबकि एक सह-मालिक के मामले में केवल अपने आप में स्वामित्व का दावा करना शायद ही पर्याप्त हो क्योंकि सभी सह-मालिकों की ओर से एक सह-मालिक का कब्जा लिया जाता है, निष्कासन का मामला सफलतापूर्वक स्थापित होने पर सह-मालिक को सफल होने का अधिकार मिलेगा। [पैरा 56] [983-सी-एच]

1.18 . ताकि एक मुकदमा अनुच्छेद 96 के तहत आ सके, एक प्रबंधक द्वारा एक स्थानांतरण होना चाहिए जिसमें एक मुतवल्ली [2023] 6 एस. सी. आर. शामिल होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक वक्फ का। यह मूल्यवान विचार के लिए होना चाहिए। इसके लिए

पूर्व मंजूरी की आवश्यकता एक वैधानिक आदेश है जिसकी कल्पना एक निश्चित और उदात्त उद्देश्य के साथ की गई है और जिसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप केवल एक शून्य लेनदेन हो सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसी बिक्री को मान्य करने में सक्षम बनाता हो। में। वास्तव में, उत्तरदाता 2 और 4 का रुख यह है कि स्थानांतरण अमान्य थे। इसलिए, अधिकारियों ने इस आधार पर भी कार्रवाई की है कि लेन-देन अमान्य था और इसलिए उक्त आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। [पैरा 61] [985-जी-एच; 986-ए-डी]

1.19 . इस आधार पर आगे बढ़ना कि 1974 में निष्पादित बिक्री एक अमान्य लेनदेन था। सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 96

अमान्य लेन-देन के मामले में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। उक्त आधार पर चल रहे विवादित आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण का दावा करने वाले वक्फ के लाभार्थी के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। जबकि वह एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वक्फ में "रुचि रखने वाला" माना जा सकता है।

धारा 2 (के) के अर्थ के भीतर, दोनों इस तथ्य के कारण कि वह आर्थिक या अन्य लाभ का प्राप्तकर्ता है और वह वाकीफ का वंशज भी हो सकता है, यह उसे न्यासी के रूप में वर्णित करने से बहुत दूर है। वक्फ विलेख के संदर्भ में लाभार्थी को लाभ मिल सकता है। उसे इस संबंध में अधिकार दिए जा सकते हैं। [पैरा 62-64] [986-D-F; 987-A-B]

1.20 . 'प्रत्ययी' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए 'प्रत्ययी संबंध' के मामले में भी ऐसा ही है। वस्तुतः, धारा 88

न्यास अधिनियम, 1882 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति

एक प्रत्ययी चरित्र में और साबीर अली खान बनाम के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और

अन्य

वक्फ विलेख के संदर्भ में अधिकारों से संपन्न। दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं लिया जाता है। निस्संदेह, यह कहा जा सकता है कि वक्फ में संपत्ति सर्वशक्तिमान में निहित है, इसलिए एक चिंता होनी चाहिए और निस्संदेह, एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस तरह से कार्य करे कि वक्फ के उद्देश्य को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन एक लाभार्थी एक ट्रस्टी की तरह नहीं है, जो एक ट्रस्टी के रूप में अपने चरित्र पर कब्जा कर लेता है, ट्रस्टी के रूप में अपने चरित्र को त्यागने और अतिक्रमणकारी या व्यक्ति के वस्त्र पहनने के प्रतिबंध के तहत आता है। शत्रुतापूर्ण शीर्षक का दावा करना। ऐसा नहीं है कि बिक्री से पहले किसी भी क्षमता में संपत्ति पर लाभार्थी का कब्जा था। [पारस 65-67] [987-सी-डी; 988-एच; 989-ए-बी; 989-सी]

1.21 . दूसरी बिक्री में, पूर्व सुतवल्ली, अर्थात् , क्यू. ए., एक समझौते के बल पर बिक्री विलेख में प्रवेश किया और

1.22 . यह तर्क कि अधिनियम की धारा 107 अपीलार्थी को सीमा की सीमा को पार करने में सहायता करेगी, अपील नहीं करता है। अधिनियम की धारा 107, निस्संदेह, घोषणा करती है कि सीमा अधिनियम, 1963 में कुछ भी किसी भी वक्फ में शामिल अचल संपत्ति के कब्जे या ऐसी संपत्ति में किसी भी हित के कब्जे के लिए किसी भी मुकदमे पर लागू नहीं होगा। [पैरा 69] [989-एफ-जी]

1.23 . यह अधिनियम 01.01.1996 पर लागू हुआ। पहली बिक्री 14.10.1960 पर की गई थी। दूसरी बिक्री पर प्रभाव पड़ा था

26.09.1974 . जहाँ तक पहली बिक्री का संबंध है, अनुच्छेद 96 [2023] 6 एस. सी. आर. नहीं कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवा में लगाया जाए क्योंकि स्थानांतरण सुतवल्ली द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं था। अनुच्छेद 65 को लागू करने के लिए दरवाजे खुले थे। जहाँ तक दूसरी बिक्री का संबंध है, जो वर्ष 1974 में प्रभावी हुई थी, अनुच्छेद 96 लागू नहीं था, स्वीकृति के लिए एकमात्र अन्य प्रतिस्पर्धी अनुच्छेद, अनुच्छेद 65 प्रतीत होता है। अनुच्छेद 65 को लागू करना और प्रतिकूल अधिकार के रूप में हस्तांतरण की तारीख से, बारह साल की समाप्ति पर, यानी 1986 में सीमा अधिनियम की धारा 27 को लागू करना शुरू हो जाएगा। धारा 65 के अर्थ के भीतर जो भी शीर्षक बचा रहेगा, वह समाप्त हो जाएगा। अधिनियम को केवल 01.01.1996 से लागू किया गया था। धारा 107 के उद्देश्य को यह नहीं समझा जा सकता है कि यह एक समाप्त हो चुके अधिकार को पुनर्जीवित करेगा क्योंकि कानून के तहत दूसरी बिक्री की तारीख से कुछ भी समय के चलने के रास्ते में नहीं था। [पैरा 70] [989-जी-एच; 990-ए-सी]

1.24 . इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीमा का कानून वही है जो प्रचलित है।

सूट की तारीख। 1997 को उस तारीख के रूप में लेते हुए, जिस पर एक मुकदमा दायर किया जाता है, और अधिनियम को लागू करते हुए, जो वादी को सीमा के कानून की अवहेलना करने में सक्षम बनाता है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि क्या था

पहले के कानून के तहत बुझा दिया गया पुनर्जीवित होगा। [पैरा 71] [990 सी-डी] 1.25 .
उच्च न्यायालय में मुद्दा अनिवार्य रूप से इस सवाल के इर्द-गिर्द केंद्रित था कि क्या अनुच्छेद 96 लागू होगा और लागू होगा

उसी प्रकार, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित अनुच्छेद 65 के प्रभाव को प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 96 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। भले ही अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही के संबंध में, चाहे वह धारा 52 हो, यदि कार्रवाई की तारीख को, सीमा अधिनियम की धारा 27 के आधार पर संपत्ति में स्वामित्व उस व्यक्ति के पास निहित था जो कब्जे में था, तो इसकी अनदेखी करने की अनुमति नहीं हो सकती है।

अधिकार जो अर्जित किया गया था। [पैरा 72] [991-ए-बी]

टी. कलियमूर्ति और एक अन्य वी. पाँच गोरी थाईक्ल वक्फ और अन्य (2008) 9 एस. सी. सी. 305: [2008] 11 एससीआर 758;

सी. बीपतुम्मा और अन्य बनाम। वेलासरी

शंकरनारायण कदम्बोलिथाय और अन्य आकाशवाणी

1965 एससी 241: [1964] एससीआर 836-पर निर्भर।
चिंतामणि साहू (एल. आर. द्वारा मृत) और अन्य बनाम। उड़ीसा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती के आयुक्त बीर अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान एक अन्य

उड़ीसा और अन्य 1983 उड़ीसा 205; अनीसुर रहमान और अन्य बनाम। शेख अबुल हयात एयर 1965 पटना 390-स्वीकृत।

श्री मोहम्मद इस्माइल फारुकी बनाम। भारत संघ और

अन्य एआईआर 1995 एससी 605: [1994] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1; मस्जिद जिसे मस्जिद शाहिद गंज के नाम से जाना जाता है, और अन्य बनाम। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर और एक अन्य आकाशवाणी 1940 पी. सी. 116; फकीर मोहम्मद। शाह बनाम। काजी फासिहुद्दीन अंसारी और अन्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 713; मोअत्तर रज़ा और अन्य बनाम। के संयुक्त निदेशक

एकीकरण, बरेली में यू. पी. शिविर और अन्य 1970 ए. आई. आर. इलाहाबाद 509; खिल्ली राम बनाम। राजस्थान राज्य

(1985) 1 एससीसी 28: [1985] 1 एस. सी. आर. 1136; (श्रीमती) अमीना खातून बनाम। तीसरा अतिरिक्त। डी. जे. फारुखाबाद और अन्य

1987 सभी एलजे 1282; छेदी लाल मिश्रा (मृत) एलआरएस के माध्यम से। वी. सिविल जज, लखनऊ और अन्य (2007) 4 एस. सी. सी. 632: [2007] 2 एससीआर 568; के. एस. विश्वम अय्यर (मृत) एलआरएस के माध्यम से। वी. राज्य वक्फ बोर्ड, मद्रास (1994) पूरक। 2 एस. सी. सी. 109; वली मोहम्मद (मृत) एल. आर. एस. वी. रहमत वी (श्रीमती) और अन्य एआईआर 1999 एससी 1136: [1999] 1 एस. सी. आर. 852; फजलुल रब्बी प्रधान बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [1965] 3 एस. सी. आर. 307: ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1722; डॉ. एम. इस्माइल फारुकी और अन्य बनाम। भारत संघ (1994) 6 एससीसी 360: [1994] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1; सैयद यूसुफ यारखान और अन्य बनाम। सैयद मोहम्मद यार खान और

अन्य [1967] 2 एस. सी. आर. 318; एम. सिद्दीक (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) v. महंत सुरेश दास और अन्य (2020) 1 एस. सी. सी. 1: [2019] 18 एस. सी. आर. 1; कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम। सरकार. भारत और अन्य (2004) 10 एस. सी. सी. 779: [2004] 1 पूरक। एससीआर 255; ठाकुर मोहम्मद। इस्माइल बनाम। ठाकुर साविर

अली एयर 1962 एससी 1722: [1963] एससीआर 20; अहमद जी. एच. अरिफ और अन्य बनाम। संपत्ति कर आयुक्त, कलकत्ता ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1691: [1970] एस. सी. आर. 19; चिन्ना जीयंगर मठ, तिरुपत बनाम। सी. वी. पुरुषोत्तम और अन्य ए. आई. आर. 1974 ए. पी. 175; वक्फ के लिए विशेष अधिकारी

मद्रास बनाम. सुब्रमण्यम और अन्य ए. आई. आर. 1977 मद्रास 79; अब्दुल फतह मोहम्मद इशाक बनाम।

धर [2023] 6 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चौधरी 22 भारतीय अपील 76; यू. पी. सुन्नी सेंट्रल

वक्फ बोर्ड और एक अन्य V. हसन जहाँ बेगम और

एक और ए. आई. आर. 1977 ऑल 18; सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी

शिक्षा और एक अन्य वी। आदित्य बंदोपाध्याय और

"मुस्लिम कानून के सिद्धांतों" पर मुल्ला (22 बां)

संस्करण)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पैरा 8

(वी)

[1994] 5 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

(vi)

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 1956 एससी 713

[1985] 1 एससीआर 1136

पैरा 8

(xvi)

संदर्भित किया गया है

[2007] 2 एससीआर 568

पैरा 9

(vi)

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

(vi)

(1994) 2 पूरक। एस. सी. सी 109

संदर्भित किया गया है

[1999] 1 एससीआर 852

पैरा 9

(vi)

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

1965 3 एससीआर 307

पैरा 11

[1994] 5 पूरक। एससीआर 1

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

(1967) 2 एससीआर 318

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2019] 18 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2004] 1 पूरक। एससीआर 255

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1963] एससीआर 20

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[1970] एस. सी. आर 19

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2008] 11 एससीआर 758

उस पर भरोसा करें

पैरा 72

[2011] 11 एससीआर 1028

संदर्भित किया गया है

पैरा 65

[1964] एससीआर 836

उस पर भरोसा करें

पैरा 71

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं।

7087 2009 से।

उच्च न्यायालय के 02.05.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. सं. में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य। 595 और 2003 का 596।

साबीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और

अन्य

सलमान खुशिद, वरिष्ठ अधिवक्ता।, इरशाद अहमद, सुश्री लुबना एन, सुश्री कामना सिंह, अनुराग रावत, शेख मोहम्मद हनीफ, अमन खुल्लर, सुश्री सोम्या चतुर्वेदी, खान, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। पी. एस. पटवालिया, एस. आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, गौरव अग्रवाल, एजाज मकबूल, सुश्री आकृति चौबे, सुश्री तान्या श्री, सुश्री हर्षिका वर्मा, सैफ जिया, सैयद मोहम्मद। मुजताबा, प्रदीप मिश्रा, मंगल प्रसाद, प्रतीक यादव, पृथ्वी यादव, मित्र राव, गौरव, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल संशोधन सं. में पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है। 595 और 2003 का 596। द.

बदले में, वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा हमारे सामने पहले प्रतिवादी द्वारा दायर अपील पर पारित आदेश के खिलाफ संशोधन का निर्देश दिया गया था। पहले प्रतिवादी ने फिर से कलेक्टर बुलंदशहर द्वारा पारित आदेश जारी किया। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के तहत पारित किया गया था वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 52 (2) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। अंत में, हमें इस स्तर पर यह बताना चाहिए कि कलेक्टर वक्फ बोर्ड के नियंत्रक द्वारा विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने और वक्फ बोर्ड को देने के लिए की गई मांग के आधार पर कार्य कर रहा था। यह माँग अधिनियम की धारा 52 (1) के तहत की गई थी।

2. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश द्वारा, उसने विभिन्न आधारों पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था। विवादित आदेश द्वारा

अपीलार्थियों द्वारा उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर संशोधनों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, हालांकि, इस आधार पर कि अपील में पहले प्रतिवादी ने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार को पूर्ण किया था।

3. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सलमान खुशीद और प्रथम प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया और दूसरे प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सिंह-सहायक सर्वेक्षण आयुक्त, वक्फ, बुलंदशहर और चौथे प्रतिवादी-कलेक्टर, वक्फ, बुलंदशहर को सुना है।

तथ्य

निम्नलिखित वंशावली चार्ट निर्धारित करके शुरू करते हैं:

4. हम

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सैयद मोहम्मद अकबर अली खान

कासिम अली खान

सैयद कासिम अली खान

सैयद रजा

अली खान

सैयद मोहम्मद। अली खान

मोहम्मद

अहमद अली खान

सईद शुजात अली खान सज्जाद अली खान

(उत्त

रदाता संख्या 1)

(उत्तरदाता संख्या 1)

5. पार्टियाँ शिया मुसलमान हैं। मोहम्मद. अकबर अली खान ने बताया कि

26.07.1934 दिनांकित विलेख द्वारा एक वक्फ-अलाल-औलाद बनाएँ। उन्होंने खुद को पहले मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किया। हालाँकि, उन्होंने वर्ष 1948 में एक नलकूप और आसपास की कुछ भूमि के संबंध में एक बिक्री विलेख को निष्पादित करने का इरादा किया। अकबर अली खान के बेटों में से एक कासिम अली खान ने बिक्री विलेख पर आक्षेप लगाते हुए 1950 का ओएस नंबर 1 दायर किया। निचली अदालत ने उक्त मुकदमे का फैसला सुनाया और उच्च न्यायालय द्वारा 11.07.1962 पर दिए गए अपने फैसले द्वारा डिक्ली की पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के दौरान यह अभिनिर्धारित किया कि अकबर अली खान ने एक वैध और प्रभावी वक्फ बनाया था, जिसकी आवश्यकता थी -

शिया मुसलमान जो वे थे। 16.12.1958 पर अकबर अली खान का निधन हो गया। वे अपने पीछे तीन बेटे कासिम अली खान और काजिम अली खान छोड़ गए।

और रजा अली खान। ऐसा प्रतीत होता है कि कासिम अली खान ने मुतवल्ली के रूप में पदभार संभाला। वक्फ रजिस्टर में उनका नाम दर्ज था। हालाँकि, उनके छोटे भाइयों, यानी काजिम अली खान और रज़ा अली खान को उनके भाई मिल गए।

संपत्ति के संबंध में राजस्व अभिलेखों में भूमिधर के रूप में परिवर्तित नाम। इसके कारण कासिम अली खान ने फिर से दूसरा मुकदमा दायर किया, यानी 1959 का ओएस नंबर 421। उन्होंने यह घोषणा करने की मांग की कि वादी अनुसूची संपत्ति एक वक्फ संपत्ति थी। उन्होंने अपने दो भाइयों के नाम हटाने से भी राहत मांगी। उक्त मुकदमे का फैसला 21.05.1962 पर वादी के पक्ष में किया गया था। मोहम्मद. काजिम अली खान ने

मुकदमे के लंबित रहने के दौरान 14.10.1960 पर अपना कथित एक-तिहाई हिस्सा मोहम्मद को हस्तांतरित कर दिया। अहमद अली खान जो उनके भतीजे थे, रजा अली खान के बेटे थे। इसे पहली बिक्री कहा जाएगा।

6. अपील में रिमांड के बाद, जब मुकदमा लंबित था,

गाँव में एकीकरण की कार्यवाही शुरू हुई। कानून के तहत, मुकदमे को समाप्त कर दिया जाना था। सूट बंद हो गया। श्री कासिम अली खान ने अन्य बेटों के नामों को हटाने की मांग करते हुए आपत्ति दर्ज की। , उनके भाई। यह इस आधार पर किया गया था कि संपत्तियां वक्फ साबीर अली खान बनाम थीं।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

संपत्तियाँ। समेकन अधिकारी ने आपत्ति स्वीकार कर ली। उन्होंने निर्देश दिया कि वक्फ की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में की जाए। यह उनका तर्क था कि वक्फ के निर्माण पर, संपत्तियाँ सर्वशक्तिमान में निहित थीं और पहली बिक्री कमजोर थी। श्री कासिम अली खान और श्री रजा अली खान द्वारा दायर अपील को निपटान अधिकारी ने खारिज कर दिया। उनके द्वारा दायर संशोधन को भी 29.01.1969 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। हालाँकि, यह प्रतीत होता है कि एक आवेदन, मांग रहा है

हालाँकि, पुनर्स्थापना के लिए आवेदन दायर किया जाने लगा। यह उक्त पुनर्स्थापना आवेदन में है, तीन भाइयों के बीच 13.02.1974 पर एक समझौता किया गया था। , कासिम अली खान, कासिम अली खान और रजा अली खान। समझौता इस आधार पर आगे बढ़ा कि वक्फ एक कागजी लेनदेन था। यह आगे का आधार था कि वक्फ था इस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई और आगे कहा गया कि भूखंडों के भूमिदार कासिम अली खान, रजा अली खान और मोहम्मद अहमद अली खान (अंतिम विदेशी) थे, जो एक-एक तिहाई हिस्से के हकदार थे। डिप्टी कलेक्टर, समेकन ने समझौते को स्वीकार कर लिया, योग्यता के आधार पर पारित आदेश 29.01.1969 को दरकिनार कर दिया, और समझौते के आधार पर संशोधन का निपटारा किया। कोई मंजूरी नहीं मिली थी।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 49 ए के अर्थ में वक्फ बोर्ड से (इसके बाद संक्षेप में '1960 अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। शिया वक्फ बोर्ड कोई पार्टी नहीं थी। हम यह भी देखते हैं कि 02.03.1972 दिनांकित आदेश को अलग कर दिया गया था। श्री कासिम अली द्वारा 26.09.1974 पर समझौते के आधार पर एक बिक्री विलेख निष्पादित किया गया।

सुजात अली खान को वापस ले लिया गया। इसके बाद, श्री सज्जाद अली खान, जो श्री कासिम अली खान के एक अन्य पुत्र थे और जिन्होंने वक्फ के लाभार्थी होने का दावा किया था, ने यू. पी. शिया वक्फ बोर्ड के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण पर सवाल उठाया, दोनों श्री कासिम अली खान, उनके पिता और उनके चाचा द्वारा। , श्री कासिम अली खान। उन्होंने [2023] 6 एस. सी. आर. में प्रवेश किए गए समझौते को एक बादल के नीचे लाने की भी मांग की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1974 की रिट याचिका (सी) संख्या 5874 को वापस लेने के अलावा उप निदेशक, समेकन के समक्ष उनके द्वारा। वक्फ बोर्ड के नियंत्रक ने 16.07.1997 दिनांकित आदेश पारित किया। उक्त आदेश द्वारा, उन्होंने अधिनियम की धारा 52 (1) को लागू किया और कलेक्टर को अनधिकृत लोगों से विवादित भूमि की वसूली और कब्जा देने का निर्देश दिया।

रहने वाले, अर्थात्, श्री सैयद मोहम्मद अहमद अली खान और श्री मोहम्मद

अली खान, जो श्री रजा अली खान के पुत्र थे। वे अपीलों में पहले उत्तरदाता हैं और उनके रूप में संदर्भित हैं। इसके बाद कलेक्टर ने 31.12.1997 दिनांकित आदेश पारित किया, जिसमें उत्तरदाताओं को तीस दिनों के भीतर बोर्ड को संपत्ति का कब्जा देने का निर्देश दिया गया। इस आदेश को अपीलों में पहले उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती दी गई।, बुलंदशहर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष कथित अनधिकृत रहने वाले। उक्त अपीलों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी ने 1998 की रिट याचिका (सी) संख्या 23414 दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि यह वक्फ न्यायाधिकरण था जिसका अधिकार क्षेत्र था न कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। इस तर्क को उच्च न्यायालय का समर्थन मिला और यह पाया गया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया गया। इसके बाद, पहले प्रतिवादी ने वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष 2002 की अपील संख्या 2 और 2002 की अपील संख्या 3 दायर की। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, वक्फ ट्रिब्यूनल ने अपील की अनुमति दी और कलेक्टर के आदेश को दरकिनार कर दिया गया। यह उक्त आदेश है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करके की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

डब्ल्यू. ए. क्यू. एफ. न्यायाधिकरण का अंत

7 .

आई.

अधिनियम की धारा 52 (1) के तहत, बोर्ड को पहले संतुष्ट करना था

इस तरह से जो निर्धारित किया गया था, जांच करने के बाद कि संपत्ति वक्फ रजिस्टर में दर्ज है और आगे यह कि संपत्ति को बोर्ड की किसी भी पूर्व अनुमति के बिना अलग कर दिया गया था। इसके बाद, मामला यह होगा कि

कब्जे की वसूली के लिए कलेक्टर को भेजा गया।

ii.

अभिलेख और उनके द्वारा दाखिल की गई एक वास्तविक प्रति को देखने के बाद अपीलार्थी (कागजात सं. 42 सी और 53 सी2), यह पाया गया कि आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि बोर्ड ने कोई जांच की थी।

ली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

बोर्ड जाँच के बाद खुद को संतुष्ट नहीं कर पाया था। यह निष्कर्ष इस आधार पर दर्ज किया गया था कि बोर्ड से मांगे गए रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं था।

रिकॉर्ड में शामिल एक वरिष्ठ वक्फ निरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वरिष्ठ वक्फ निरीक्षक ने वास्तव में यह नहीं देखा था कि संपत्ति वक्फ रजिस्टर में दर्ज थी या नहीं। नियंत्रक ने नहीं किया था

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुद को संतुष्ट करें

अधिनियम की धारा 52 (1)।

अपनाई गई प्रक्रिया अवैध थी। कोई अधिकारी नहीं था

अधिनियम के तहत नियंत्रक के रूप में जाना जाता है। धारा 52 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है। यह स्थापित करने के लिए कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई कि बोर्ड ने अपनी शक्ति किसी भी अधिकारी को हस्तांतरित कर दी जिसे नियंत्रक के रूप में जाना जाता है। द्वारा पारित आदेश

नियंत्रक अधिकारिता के बिना था।

केवल सात दिनों की अवधि दी गई थी, जो अवैध है।

वक्फ बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका में प्रतिवादियों के कब्जे को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। यह आगे स्वीकार किया गया कि उत्तरदाता संपत्ति का उपयोग अपने हित और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में कर रहे थे। उत्तरदाताओं को पाया गया कि

उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 49 ए और धारा 51 के अपवाद अधिनियम से। दोनों अधिनियम वक्फ के विषय पर विशेष अधिनियम थे। ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं था कि किसी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नए अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।

उच्च न्यायालय के कार्य

अपीलार्थी के इस तर्क में योग्यता है कि उप निदेशक के समक्ष समझौता किया गया था,

समेकन, एक सांठगांठ होने के कारण, वक्फ को हरा नहीं सका। एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ।

वक्फ बोर्ड की अनुपस्थिति में, उप निदेशक द्वारा पारित आदेश, समझौते पर कार्य करने वाला समेकन 1960 के यू. पी. अधिनियम की धारा 69 को देखते हुए अमान्य था।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री कासिम अली खान द्वारा 29.06.1974 पर की गई बिक्री

iii.

(दूसरी बिक्री) इस कारण से भी अमान्य थी कि वक्फ बोर्ड की कोई अनुमति धारा के तहत प्राप्त नहीं की गई थी।

491960 के यू. पी. अधिनियम का ए. समान रूप से, श्री कासिम अली खान द्वारा वर्ष 1960 (पहली बिक्री) में निष्पादित बिक्री, जो एक लाभार्थी थे, जिन्हें वक्फ संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं था,

शून्य था।

श्री

सैयद मोहम्मद अहमद अली खान और श्री सैयद

iv.

मोहम्मद अली खान वक्फ-अल-अल-अलाद में लाभार्थी थे। अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि एक लाभार्थी वक्फ संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकता है, यह पाया गया कि स्वामित्व प्रतिकूल रूप से अधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

श्री मोहम्मद इस्माइल फारूकी बनाम पर भरोसा करते हुए। संघ

वी.

भारत और अन्य 1 और मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है

मस्जिद शाहिद गंज, और अन्य बनाम। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर और एक अन्य, यह पाया गया कि प्रतिकूल कब्जे से उपाधि प्राप्त की जा सकती है

वक्फ संपत्ति पर।

एक प्रत्ययी संबंध में एक व्यक्ति या एक, जिसमें

vi.

संपत्ति न्यास में निहित थी, प्रतिकूल रूप से स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती थी न्यास संपत्ति पर अधिकार। एक मुतवल्ली, तदनुसार, उक्त सिद्धांत पर, वक्फ संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता था [फकीर मोहम्मद देखें। शाह बनाम। काजी फासिहुद्दीन अंसारी और अन्य 3]। कि एक सह-मालिक भी विश्वास पर प्रतिकूल कब्जा करके अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है।

संपत्ति, कानून में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त पाई जाती है।
एक लाभार्थी सह-स्वामी नहीं है और इसलिए, सिद्धांत

vii.

कि सह-स्वामी किसी अन्य सह-स्वामी के हिस्से पर प्रतिकूल कब्जा करके अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है, एक लाभार्थी पर लागू नहीं था। एक लाभार्थी ने नहीं रखा था

विश्वास में संपत्ति।

" वक्फ के हर मामले में, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी,

viii.

संपत्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर या स्वयं वक्फ में निहित है।

1995 एससी 605

1940 पीसी 116 1956 एससी 713 ली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

संस्था या एक आर्थिक आधार, जो अभी लागू है"। उच्च न्यायालय ने मोअत्तर रज़ा और अन्य बनाम में रिपोर्ट किए गए निर्णय में एक पूर्ण पीठ द्वारा व्यक्त किए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से समर्थन प्राप्त किया। के संयुक्त निदेशक

बरेली और अन्य स्थानों पर एकीकरण, यू. पी. शिविर।

सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 96 में एक अवधि का प्रावधान है। एक मुस्लिम धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती के प्रबंधक द्वारा एक सूट के लिए बारह साल, अन्य बातों के साथ-साथ, एक पिछले प्रबंधक द्वारा मूल्यवान विचार के लिए हस्तांतरित कब्जे की वसूली के लिए। श्री कासिम अली खान (पहली बिक्री) द्वारा निष्पादित बिक्री इसके दायरे में नहीं आएगी क्योंकि वह मुतवल्ली/प्रबंधक नहीं थे।

श्री कासिम अली खान, जिन्हें मुतवल्ली के रूप में जाना जाता था, द्वारा 1974 में निष्पादित बिक्री विलेख के संबंध में, न्यायालय ने सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 और 96 की परस्पर क्रिया पर गौर किया। यह पाया गया कि अनुच्छेद 96 अमान्य हस्तांतरण के मामले में लागू नहीं होगा। किसी हस्तांतरण के वैधानिक आवश्यकता के उल्लंघन के कारण अमान्य होने की स्थिति में, हस्तांतरणकर्ता का प्रतिकूल कब्जा हस्तांतरण की तारीख से शुरू हो जाएगा। यदि पुनर्प्राप्ति के लिए सूट

बारह वर्ष की अवधि के भीतर कब्जा स्थापित नहीं किया गया था। अनुच्छेद 65 के तहत वर्षों तक, संपन्न संपत्ति की वसूली के लिए प्रबंधक के अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

सीमा अधिनियम की धारा 27।

अनुच्छेद 96 पर रखी जाने वाली सही व्याख्या यह है कि जहां धारा 27 के तहत अधिकार की वसूली का अधिकार नहीं खोया गया था, वहां अधिकार की वसूली के मुकदमों तक इसकी सीमा सीमित कर दी जाए।

न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थियों ने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार प्राप्त किया था, सही पाया गया। द. वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 66 जी के आधार पर विवाद,

पीछे हटा दिया गया था, हालांकि यह तीस साल की अवधि के लिए प्रदान किया गया था। यह इस आधार पर था कि उक्त अधिनियम को उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं किया गया था।

एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 107, जिसमें सीमा अधिनियम शामिल नहीं है, अपीलार्थी के लिए बहुत कम उपयोगी पाई गई। एक व्यक्ति मुतवल्ली के माध्यम से प्रतिकूल अधिकार का दावा नहीं किया जाता है। प्रत्यर्थियों के प्रतिकूल कब्जे से पकने के अधिकार को अधिनियम की धारा 107 का आह्वान करके पराजित नहीं किया जा सकता था।

न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्त किया गया विचार कि वक्फ बोर्ड जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध था और इस तरह की जांच नहीं की गई थी, गलत पाया गया। अपीलार्थी का यह तर्क कि वक्फ पंजीकृत था, विवादित नहीं था, और यह भी विवादित नहीं था कि बिक्री के लिए कोई पूर्व मंजूरी नहीं थी, योग्यता के साथ पाया गया था।

यह नोट किया गया कि निरीक्षक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वक्फ को वक्फ संख्या 1456 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो पाठ गलत के रूप में स्थापित नहीं किया गया था। आगे यह पाया गया कि उत्तरदाताओं ने ऐसा कोई मामला स्थापित नहीं किया था कि वक्फ वक्फ रजिस्टर में पंजीकृत नहीं था। इसलिए, यह पाया गया कि धारा 52 के तहत कोई जांच नहीं होने के आधार पर नियंत्रक के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी पाया गया कि इसे इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था कि दिमाग का कोई उपयोग न हो।

खिल्ली राम बनाम में बताए गए निर्णय का प्रभाव। राजस्थान राज्य 3, यह पाया गया कि वक्फ रजिस्टर में प्रविष्टि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील में सवाल के लिए खुली नहीं होगी। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष है। न्यायाधिकरण के पास व्यापक शक्तियाँ हैं और वह इस प्रश्न पर विचार कर सकता है। न्यायाधिकरण बोर्ड द्वारा जारी अनुरोध आदेश की वैधता पर विचार कर सकता है। ये (श्रीमती) में रिपोर्ट किए गए निर्णय में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में व्यक्त किए गए विचार हैं। अमीना खातून बनाम। तीसरा अतिरिक्त। डी. जे. फारुखाबाद और अन्य। उच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की

उक्त दृष्टिकोण के साथ।

न्यायाधिकरण ने नोटिस को दोषपूर्ण पाते हुए गलती की नोटिस नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय

इस आधार पर कि तीस दिनों का

1282 ली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

उत्तरदाताओं का यह तर्क कि वक्फ के वरिष्ठ निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट एकपक्षीय रिपोर्ट थी और उन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया था, तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया। हालांकि, यह पाया गया है कि नियंत्रक ने पाया था कि विचाराधीन संपत्ति वक्फ संपत्ति थी, वक्फ पंजीकृत था और अंत में, हस्तांतरण अमान्य था। अनुमति के अभाव में। यह विशेष रूप से पाया गया है कि 'तथ्यों पर कोई विवाद नहीं दिखाई देता है'। कोई पूर्वाग्रह नहीं है, यह उत्तरदाताओं के लिए आगे पाया जाता है, विशेष रूप से

न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया पूरा अवसर, विशेष रूप से जब यह तर्क नहीं दिया गया था कि वक्फ पंजीकृत नहीं था या संपत्ति वक्फ संपत्ति या वह अनुमति नहीं थी

स्थानांतरण से पहले लिया गया था।

हालांकि, यह पाया गया कि इस निष्कर्ष को देखते हुए कि उत्तरदाताओं ने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार प्राप्त किया था, संशोधन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं थी और तदनुसार, उन्हें खारिज कर दिया गया था।

एपेल्लांट के नियम

अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 96 लागू होता है। सीमा की अवधि 1996 से या उस तारीख से शुरू होगी, जब अपीलकर्ता श्री सज्जाद अली खान को मुतवल्ली नियुक्त किया गया था, क्योंकि श्री कासिम अली खान के इस्तीफा देने या वर्तमान मुतवल्ली श्री सज्जाद अली खान की नियुक्ति की तारीख से बारह साल पूरे नहीं हुए थे। इसलिए, श्री सैयद मोहम्मद अहमद अली खान प्रतिकूल कब्जे से उपाधि प्राप्त नहीं कर सके। सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 लागू नहीं हुआ। श्री सैयद अहमद अली खान का दावा समझौते पर आधारित था।

दिनांकित 13.02.1974। यह दिनांकित 14.10.1960 बिक्री विलेख पर आधारित नहीं था। उक्त बिक्री विलेख के तहत अधिकार, यदि कोई हो, प्राप्त हुआ

[2023] 6 एस. सी. आर. के दौरान उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने के कारण इसे बुझा दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समेकन कार्यवाही और इसके निर्णय भी

तीन समेकन न्यायालय।

श्री सैयद के प्रतिकूल कब्जे के दावे के संबंध में

iii.

मोहम्मद अली खान ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 65 एक था

सामान्य अनुच्छेद और यह अनुच्छेद 96 है, जो लागू होगा। अपीलार्थी को मुतवल्ली नियुक्त किया गया। अवधि चलनी शुरू हो जाएगी, जब वह इस तरह से नियुक्त किया गया था या की तारीख से

उनके द्वारा 1996 में शिकायत दर्ज कराई गई।

iv.

उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि वक्फ का अधिकार सीमा की धारा 27 के आधार पर समाप्त हो गया था

एकट करें। चूँकि कब्जे के लिए मुकदमा पहले के मुतवल्ली से हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ था, इसलिए कब्जा बन जाएगा

मृत्यु या त्यागपत्र की तारीख से प्रतिकूल पहले की सीमा के अनुच्छेद 134 बी के तहत मुतवल्ली

अधिनियम और बारह वर्ष की समाप्ति पर, जैसा कि प्रावधान किया गया है

अनुच्छेद 96, और बिक्री विलेख की तारीख से नहीं।

अपीलार्थी ने आगे तर्क दिया कि उत्तरदाताओं को

वी.

लाभार्थी, प्रतिकूल कब्जे से अधिकार प्राप्त नहीं कर सके,

वक्फ संपत्ति।

रिलायंस को निम्नलिखित निर्णयों पर रखा गया था:

vi.

छेदी लाल मिश्रा (मृत) एलआरएस के माध्यम से। वी. सिविल

ए।

जज, लखनऊ और अन्य? ;

बी।

के. एस. विश्वम अय्यर (मृत) एलआरएस के माध्यम से। वी. राज्य वक्फ बोर्ड, मद्रास; और

वली मोहम्मद (मृत) एलआरएस द्वारा। वी. रहमत बी (श्रीमती)

सी.

और अन्य।

10. श्री पी. एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ वकील, अपनी ओर से उपस्थित हुए अपीलों में प्रधान सं. 1 निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ करता है:

कोई वैध वक्फ नहीं बनाया गया है क्योंकि वक्फ ने कभी काम नहीं किया उस पर। उन्होंने कभी भी आवश्यकता के अनुसार खुद को संपत्ति से अलग नहीं किया।

मुसलमान शी से संबंधित मुस्लिम कानून के तहत। इसके तहत कानून, यह अनिवार्य है कि चरित्र में परिवर्तन होना चाहिए

7) 4 एस. सी. सी. 632

पूरक। (2) एस. सी. सी. 109 1999 एस. सी. 1136 साबीर अली खान बनाम

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

संपत्ति का अधिकार। वक्फ द्वारा उत्परिवर्तन रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 16.12.1958 पर उनकी मृत्यु तक संपत्ति व्यक्ति के नाम पर रही। इसके बाद संपत्ति को उनके तीन बेटों के नामों में बदल दिया गया। वस्तु पर निर्भरता रखी गई है

वक्फ दिनांकित 26.07.1934। इसमें संकेत दिया गया है:

" वक्फ का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ " मेरे पूर्वजों के नाम को कायम रखने और मेरी संतानों और उनकी संतानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से और

परिवार और उनकी संतानों से संबंधित रिश्तेदार, और उनकी अनुपस्थिति में, शिया गरीब, गरीब, दुखी और सैयद-अधिनियम 6 के अनुसार, मुस्लिम कानून के तहत इस उद्देश्य के लिए।

1913 के मेरे पास एक औपचारिक बयान (सिधा) द्वारा वक्फ (ट्रस्ट) में रखी गई शरिया के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति है, जिससे,

इसे अपनी संपत्ति से अलग करते हुए और इस विलेख को लिखित रूप में रखते हुए

वक्फुल औलाद (संतानों के लिए विश्वास) "।

वक्फ विलेख का खंड ई अन्य बातों के साथ प्रदान करता है: " ई. यदि भगवान न करे कि मेरी पीढ़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाए और कोई भी जीवित न रहे और न ही मेरी पत्नी पाकीज़ा बेगम या कोई अन्य पत्नी जीवित रहे, तो ऐसी स्थिति में संपन्न संपत्ति से होने वाली आय का प्रबंधन उनके द्वारा किया जाएगा।

समिति के सदस्यों को धर्मार्थ मामलों के लिए खर्च किया जाएगा।

सुविधा संकलन के टैब ए में "।

11. यह आगे तर्क दिया जाता है कि एक छोटी सी संपत्ति को छोड़कर सभी संपत्ति

सौ बीघा का पार्सल, जो वर्तमान मामले का विषय है, बेचा जा चुका है। वास्तव में, वक्फ ने स्वयं एक हिस्सा श्री मंजूर हसन को बेच दिया। अकबर अली खान के बेटों ने लगभग 4272 बीघा जमीन बेची है। न तो अपीलार्थी ने और न ही वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई। वक्फ विलेख में बकाया ऋण चुकाने के लिए वक्फ संपत्ति की आय का उपयोग करने पर विचार किया गया था। इसलिए यह वैध वक्फ नहीं था। वक्फ का निर्माण 24.07.1934 पर किया गया था, जिस समय मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, 1913 लागू था। अधिनियम में वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान नहीं था। इसके बाद मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 लागू किया गया। इसके तहत, धारा 2 (ई) के आधार पर, वक्फ-अलाल-औलाद को 1923 के अधिनियम के संचालन से बाहर रखा गया था। इसके अलावा वर्ष 1930 में मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1930 लागू किया गया था, जिसमें केवल यह घोषणा की गई थी कि 1913 का अधिनियम 1913 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले बनाए गए वक्फ पर लागू होता है।

बाद यह [2023] 6 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि यू. पी. मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1936 (इसके बाद '1936 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और 1960 अधिनियम अधिनियमित किए गए थे। न तो 1936 और न ही

1960 अधिनियम तथ्यों पर लागू होते हैं। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी के पास ऐसा मामला नहीं हो सकता है कि कथित वक्फ या तो इसके तहत दर्ज किया गया था।

1936 का अधिनियम या 1960 का अधिनियम। वक्फ का उद्देश्य संतानों और उनकी संतानों को लाभ पहुंचाना और उनकी अनुपस्थिति में शिया गरीबों को लाभ पहुंचाना है। 1936 का अधिनियम लागू नहीं हुआ और वक्फ को 1936 के अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया जा सकता था। 26.07.1934 दिनांकित वक्फ विलेख का कोई धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य नहीं है। फजलुल रब्बी प्रधान बनाम मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 0. वक्फ पंजीकृत नहीं होने के कारण, अधिनियम के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया लागू नहीं थी। यह भी शिकायत की जाती है कि कथित पंजीकरण के संबंध में अपीलकर्ताओं के अलग-अलग बयान हैं। एक ओर, यह तर्क दिया जाता है कि पंजीकरण वास्तव में 1934 में किया गया था, जिस समय 1923 का अधिनियम लागू था। उक्त अधिनियम, विशेष रूप से अपवर्जित करने के अलावा

वक्फ-अलाल-औलाद ने अपने दायरे से पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रावधान का प्रावधान नहीं किया। यह आगे बताया गया है कि सुनवाई के दौरान, एक मामला स्थापित किया गया है कि पंजीकरण 1936 के अधिनियम के तहत किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए

धारा 2 (2) (i) के माध्यम से विशिष्ट अपवर्जन, यह लागू नहीं होता है क्योंकि पूरी आय परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए जा रही थी।

1936 के अधिनियम के तहत धारा 38 में किसी भी दर पर एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उसी का पालन नहीं किया गया है। तीसरा संस्करण, यह बताया गया है कि वक्फ को 1960 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। नियंत्रक की एक रिपोर्ट, जिस पर इस न्यायालय में पहली बार भरोसा किया गया था और जिसे न्यायाधिकरण ने अस्वीकार कर दिया था, आधार नहीं हो सकती है। इसके अलावा, चूंकि पूरी आय वक्फ के वंशजों को समर्पित थी, इसलिए 1960 के अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था, इसलिए दावा आधारहीन था। यहाँ फिर से, धारा 29 ने पंजीकरण के लिए प्रक्रिया प्रदान की। उसी के अनुरूप नहीं होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता कि वक्फ 1960 के अधिनियम के तहत पंजीकृत था। 1960 के अधिनियम के लागू नहीं होने को देखते हुए, धारा 69 में अधिनियमित वक्फ से संबंधित मुकदमे या कार्यवाही के समझौते पर रोक लागू नहीं थी। धारा 45 बी में उल्लिखित वक्फ संपत्तियों की वसूली के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया

उपलब्ध नहीं था। वक्फ के पंजीकरण को स्थापित करने के लिए वक्फ रजिस्टर के उद्धरण पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था और जिसे इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 4-कलेक्टर द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया था। पंजीकरण प्रमाणन की तिथि 08.07.2008 है, जो इसके पारित होने के बाद थी

10 1965 3 एससीआर 307/एयर 1965 एससी 1722 साबीर अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

उच्च न्यायालय का आदेश। यहां फिर से अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जिन विवरणों को अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट किया जाना है, वे गायब थे। वैध पंजीकरण के अभाव में, अधिनियम की धारा 52 में प्रदान की गई संक्षिप्त प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी अपीलार्थियों के लिए। अपीलार्थियों को 22 साल की अवधि के बाद 1974 के समझौते को चुनौती देने से रोक दिया गया है। दलों ने

समझौता उसी पर काम करता है। दूसरी बिक्री हुई। स्थानांतरणकर्ता का पुत्र होने के कारण अपीलकर्ता अपदस्थ हो गया। सुज़ाद अली खान द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि उस पर दबाव नहीं डाला गया था, जिसके कारण 12.09.1974 दिनांकित आदेश अंतिम हो गया है। उत्तरदाता निरंतर और निर्बाध कब्जे में रहे हैं। यह अधिनियम लागू होने तक मुस्लिम कानून के तहत वक्फ संपत्तियों पर सीमा अधिनियम लागू था।

जिसके तहत, धारा 107 ने विशेष रूप से सीमा अधिनियम, 1963 को लागू करने पर रोक लगा दी। रिलायंस को 1940 XXI आई. एल. आर. 493 में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर रखा गया है। इसके अलावा, डॉ. एम. इस्माइल फारूकी और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन प्राप्त होता है। भारत संघ "। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 107 इसके अनुप्रयोग में संभावित थी। टी. कलियमूर्ति (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रतिवादियों के पास पहले बिक्री विलेख के बाद से मुकदमे की संपत्ति का दो-तिहाई हिस्सा है और शेष एक-तिहाई 1974 में उनके कब्जे में आया था। इस तरह के कब्जे को स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

वक्फ बोर्ड के नियंत्रक द्वारा दिनांकित 16.07.1997 आदेश;

आई.

दिनांकित बिक्री विलेख 26.09.1974;

ii.

द्वारा दायर अपील (1998 का सं. 4) में अभिकथन

iii.

जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवादी,

बुलंदशहर;

जिला न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 30.05.1998 आदेश;

iv.

2002 की वक्फ अपील सं. 3;

वी.

न्यायाधिकरण के आदेश के निष्कर्ष;

vi.

द्वारा उत्तरदाताओं के कब्जे का प्रवेश

vii.

आक्षेपित निर्णय में अपीलार्थी और, अंत में,
रिलायंस को प्रस्तुत तिथियों की सूची में रखा गया है

viii.

अपीलार्थी, जो इंगित करता है कि कलेक्टर का आदेश

यह कब्जे की वसूली के लिए था।

11 (1994) 6 एससीसी 360 [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि उत्तरदाताओं के पास 1960 से दो-तिहाई और 1974 से शेष एक-तिहाई अधिकार हैं और अधिनियम के लागू होने से पहले उत्तरदाताओं के अधिकार सामने आए। बल देते हैं। यहाँ तक कि 1974 से गिनती करते हुए भी उत्तरदाताओं ने वर्ष 1986 में, यानी 1974 से 12 वर्षों में खिताब हासिल किया है। इस प्रकार, सीमा अधिनियम, 1963 वास्तव में लागू होगा क्योंकि शत्रुतापूर्ण कब्जे के कारण अधिनियम की धारा 107 के लागू होने से पहले अधिकार पक गया था।

13. इसके बाद यह बताया गया कि मुतवल्ली की नियुक्ति से सीमा का एक नया प्रारंभिक बिंदु नहीं बना। सैयद में इस न्यायालय का निर्णय

यूसुफ यार खान और अन्य बनाम। सैयद मोहम्मद यार खान और अन्य 1 2 को उक्त मामले का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया है। उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 को सही ढंग से लागू किया था। अपील में पहला प्रतिवादी लाभार्थी नहीं है, यह अगला इंगित है

क्योंकि कोई वैध वक्फ स्थापित नहीं किया गया है। यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि कथित वक्फ कोई आय उत्पन्न कर रहा था जो किया जा रहा था

लाभार्थियों के बीच वितरित। इसका मतलब यह था कि मूल वाकीफ के तीन बेटे लाभार्थी नहीं थे और उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था। यह भी बताया गया है कि वक्फ के लाभार्थी को प्रतिकूल कब्जे का दावा करने से रोकने के लिए कानून में कोई रोक नहीं है। बार केवल मुतवल्ली पर लागू होता है। यही कारण है कि मुतवल्ली वक्फ के प्रति एक प्रत्ययी कर्तव्य रखता है। यह पहले प्रतिवादी के लिए खुला है, अंत में यह बताया गया है कि वह एक साथ अधिकार और प्रतिकूल अधिकार दोनों का अनुरोध कर सकता है। कानूनी के माध्यम से एम. सिद्दीक (मृत) पर भरोसा रखा गया था प्रतिनिधि (राम जन्मभूमि मंदिर मामला)

V. महान्त सुरेश दास और अन्य 13 और कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम। सरकार. भारत और अन्य 1 4 14.

उत्तरदायी नामों की प्रस्तुतियाँ। 2 और 4

14. उत्तरदाता सं। 2 और 4 सहायक सर्वेक्षण आयुक्त वक्फ, बुलंदशहर और कलेक्टर, वक्फ, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश हैं।

क्रमशः। विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री एस. आर. सिंह प्रस्तुत करेंगे कि बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना अकबर अली खान के तीन बेटों द्वारा समझौता आवेदन, जैसा कि 1960 के अधिनियम में विचार किया गया था, 1960 के अधिनियम की धारा 69 की आवश्यकता को देखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं था। समेकन सेटिंग के उप निदेशक का आदेश

12 (1967) 2 एस. सी. आर. 318 13 (2020) 1 एस. सी. सी. 14 (2004) 10 एस. सी. सी. 779 साबिर अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

29.01.1969 दिनांकित आदेश और 02.03.1972 दिनांकित आदेश को भी अलग रखें। अवैध था। वक्फ बोर्ड के नियंत्रक ने वक्फ बोर्ड के समक्ष शिकायत पर जांच की। उन्होंने पाया कि विवादित संपत्ति वक्फ थी

संपत्ति जो वक्फ रजिस्टर में पंजीकृत थी। यह भी पाया गया कि बोर्ड की मंजूरी प्राप्त किए बिना संपत्ति को अवैध रूप से बेचा गया था। इसके बाद, नियंत्रक ने कब्जा प्राप्त करने के लिए कलेक्टर को अनुरोध जारी किया। उच्च न्यायालय ने ठाकुर मोहम्मद में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा। इस्माइल बनाम। ठाकुर साबिर अली 15 15, कि एक वक्फ-अलाल-औलाद में, संपत्ति सर्वशक्तिमान को हस्तांतरित कर दी गई थी, लेकिन फिर भी इस बात पर विचार किए बिना कि क्या प्रतिकूल कब्जे से अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, संशोधनों को खारिज कर दिया। वे बताते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर विचार नहीं किया कि क्या सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 और 96 को ईश्वर/सर्वशक्तिमान के खिलाफ लागू किया जा सकता है। उप निदेशक द्वारा पारित आदेश, समेकन एक अमान्य था, जो 1960 के अधिनियम की धारा 69 के तहत मंजूरी से रहित था। इसका परिणाम यह हुआ कि समेकन प्राधिकरणों के पहले के निर्णयों को बहाल कर दिया गया, जिसमें यह माना गया कि विचाराधीन वक्फ एक वैध वक्फ था। उत्तर प्रदेश समेकन की धारा 49

अभिग्रहण अधिनियम, 1953, उसी मुद्दे पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किए जाने पर रोक लगाता है, जिसमें दीवानी न्यायालय के अधिकार थे। अधिनियम की धारा 51 (1) और धारा 51 (ए) के तहत दोनों बिक्री शुरू से ही अमान्य थीं। एक बार फिर समर्थन करें।

ठाकुर मोहम्मद के फैसले से लिया गया है। इस्माइल (ऊपर) और अहमद जी. एच. अरिफ और अन्य बनाम। धन कर आयुक्त,

कलकत्ता "। एक लाभार्थी/मृतवल्ली को वक्फ संपत्ति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 सीमा अधिनियम की धारा 107 को देखते हुए अधिनियम की कार्यवाही पर लागू नहीं होता था। यह आगे तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 65 मुकदमों पर लागू होता है। यह कार्यवाही पर लागू नहीं होता था। इसलिए, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 वक्फ संपत्ति पर लागू नहीं होती थी जो सर्वशक्तिमान में निहित थी। रिलायंस को छेदी लाल मिश्रा (मृत) के मामले में एलआरएस के माध्यम से इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। वी. सिविल जज, लखनऊ और अन्य "। वक्फ विलेख का अनुच्छेद-34 ए, जो धर्मार्थ उद्देश्यों पर Rs.500/- के खर्च पर विचार करता है और अनुच्छेद-34 ई, जो इस बात पर विचार करता है कि मामले में सभी वंशजों तब, वक्फ का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, वक्फ को 'वक्फ' की परिभाषा के तहत लाया जाएगा। एक शून्य दस्तावेज, जैसा कि बिक्री विलेख और समझौते के मामले में है, को इसके बिना नजरअंदाज कर दिया जाएगा

15 ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1722 16 ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1691 17 (2007) 4 एससीसी 632 [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसी को अलग रखने की आवश्यकता है। प्रत्यर्थी नं. 1 दोनों अपीलों में यह नहीं कहा जा सकता था कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे से अपने शीर्षक को परिपूर्ण किया था। उस राज्य के विरुद्ध जिसके लिए अवधि 30 वर्ष है। मुकदमा 1997 में शुरू हुआ, यानी मिलीजुली समझौते और अमान्य बिक्री विलेख की तारीख से 23 साल बाद। यह तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि वक्फ संपत्ति का प्रबंधन भगवान की ओर से वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है जो कानून के तहत सरकार के पर्यवेक्षण के तहत आता है।

विश्लेषण

15. उठाए गए तर्कों और तथ्यों को देखते हुए, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है:

1 . क्या कोई वैध शिया वक्फ था और क्या वह था

पंजीकृत?

2 . क्या समझौता दिनांकित 13.02.1974 और आदेश

दिनांकित 12.09.1974। क्या वे वैध हैं या शून्य हैं?

3 . चाहे दो बिक्री, एक 14.10.1960 पर और दूसरी 26.09.1974 पर, दोनों अपीलों में पहले प्रतिवादी के पक्ष में हो।

हमारे सामने, क्या शून्य हैं?

4 . क्या कार्रवाई सीमा द्वारा वर्जित है?

5 . क्या उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही था कि कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि यह सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 96 नहीं है, जो लागू होता है, बल्कि अनुच्छेद 65 है? तथ्यों में उक्त अनुच्छेदों के बीच क्या परस्पर क्रिया है?

6. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 का क्या प्रभाव पड़ता है?

तथ्यों में?

7. क्या अधिनियम की धारा 107 सीमा के प्रतिबंध को हटा देती है

किसी भी तरह से?

16. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि की है कि दोनों मामलों में प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह इस आधार पर है कि पहली बिक्री वर्ष 1960 में और दूसरी बिक्री वर्ष 1974 में की गई थी। यह अधिनियम 1.1.1996 से लागू हुआ। यह आगे पाया गया है कि यह अवधि दो बिक्री विलेखों की तारीखों से चलने लगी क्योंकि बिक्री शून्य थी। आगे का निष्कर्ष यह है कि सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 96 वर्ष 1960 की पहली बिक्री पर लागू नहीं होता था। उक्त बिक्री उस समय की गई थी जब सबसे बड़े भाई कासिम साबीर अली खान बनाम थे।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

मुतवल्ली। बिक्री एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी जो दूसरे शब्दों में मुतवल्ली नहीं था। इसलिए, अनुच्छेद 96 लागू नहीं हुआ। जहाँ तक दूसरी बिक्री का संबंध है, यह कासिम अली खान द्वारा अपने भतीजे को अपना एक-तिहाई अधिकार देने के लिए किया गया था, जो दूसरी अपील में पहला प्रतिवादी है। उच्च न्यायालय का आगे तर्क यह है कि दूसरा बिक्री विलेख मुतवल्ली द्वारा निष्पादित किया गया था। इसके बाद न्यायालय ने अनुच्छेद 65 और 96 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का सीमांकन किया। इसके बाद अदालत ने सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 पर भी विचार किया। अदालत ने पाया कि उचित व्याख्या यह थी कि अनुच्छेद 96 को कब्जे की वसूली के लिए मुकदमों तक सीमित रखा जाना था, जहां धारा 27 के तहत कब्जे की वसूली का अधिकार पहले ही नहीं खोया गया था। सीमा अधिनियम, 1963। अनुच्छेद 96, दूसरे शब्दों में, यह पाया गया कि यह अमान्य हस्तांतरणों पर लागू होता है। उक्त आधार पर, यह पाते हुए कि दूसरी बिक्री

अमान्य हस्तांतरण के मामले का प्रतिनिधित्व करते हुए, यह पाया गया कि अनुच्छेद 96 ने अपीलार्थी की सहायता नहीं की। यह भी पाया गया कि वक्फ के लाभार्थी के प्रतिकूल कब्जे से उपाधि प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। इस तरह की बाधा, निस्संदेह, मुतवल्ली, ट्रस्टी या सह-मालिक के मामले में मौजूद थी। उपरोक्त में से कोई भी लाभार्थी नहीं था। इस प्रकार, इस आधार पर कि दोनों अपीलों में पहला प्रत्यर्थी वक्फ के लाभार्थी थे और जिस बिक्री के तहत उन्होंने दावा किया था कि वह अमान्य पाई गई थी, इस आधार पर कार्यवाही करते हुए, अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत सीमा की अवधि पर विचार किया गया।

सीमा अधिनियम बिक्री की तारीख से चलने लगा। इसका मतलब यह था कि जब अधिनियम का जन्म 01.01.1996 पर हुआ था, तो शीर्षक प्रतिकूल कब्जे द्वारा पहले प्रतिवादी के पास निहित था। यह आगे पाया गया है कि अधिनियम की धारा 107 जिसके तहत सीमा अधिनियम लागू नहीं था अधिनियम अपीलार्थी के मामले को बचा नहीं सका।

17. यह उचित है कि हम इसके प्रासंगिक प्रावधानों का विज्ञापन करते हैं

सीमा अधिनियम। सीमा अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि

किसी भी संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए किसी भी व्यक्ति तक सीमित अवधि का निर्धारण, ऐसी संपत्ति पर 'उसका अधिकार' समाप्त हो जाएगा। सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 65 इस प्रकार है:

किस समय से

सूट का विवरण

सीमा की अवधि

दौड़ना शुरू करें

65. अचल संपत्ति के कब्जे के लिए

बारह जब

वर्ष 1 का अधिकार

या शीर्षक के आधार पर उसमें कोई ब्याज।

दी
बन जाता है

प्रतिकूल

प्रतिवा

के

वादी।

(क) जहां मुकदमा किसी शेष व्यक्ति, प्रत्यावर्तक (मकान मालिक के अलावा) या किसी योजनाकार द्वारा किया जाता है, वहां प्रतिवादी का कब्जा केवल तभी प्रतिकूल समझा जाएगा जब शेष व्यक्ति की संपत्ति, प्रत्यावर्तक या योजनाकार, जैसा भी मामला हो, कब्जे में आ जाता है;

(ख) जहां मुकदमा किसी हिंदू या मुसलमान द्वारा किया गया है जो अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार है।

हिंदू या मुस्लिम महिला की मृत्यु पर संपत्ति, प्रतिवादी का कब्जा केवल तभी प्रतिकूल माना जाएगा जब महिला की मृत्यु हो जाएगी; (ग) जहां मुकदमा एक खरीददार द्वारा एक डिक्री के निष्पादन में बिक्री पर है जब

निर्णय-बिक्री की तारीख को देनदार के कब्जे से बाहर था, खरीदार को इसका प्रतिनिधि माना जाएगा निर्णय-ऋणी जो कब्जे से बाहर था।

18. भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 का अनुच्छेद 134 बी

1963 तक अनुच्छेद 96 के स्थान पर रखने के लिए आवश्यक प्रावधान। निम्नलिखित तालिका ली के अनुच्छेद 134 बी को निर्धारित करती है।

टी, 1908 और सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 96:

" सूट का विवरण

समय की अवधि

परिसीमा परिसीमा

दौड़ें।

बारह।

134 हिंदू, मुसलमान या बौद्ध के प्रबंधक द्वारा

द.

अधिकार वर्षों की वसूली के लिए धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती

बी.

इस्ती

फा दें।

बंदोबस्ती में शामिल अचल संपत्ति

दें।

हटा

जिसे पिछले प्रबंधक द्वारा एक के लिए स्थानांतरित किया गया है

हस्तांत

रण

मूल्यवान विचार।

सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 96

" सूट का विवरण

उस समय की अवधि जिससे एफ

सीमा

भागने के लिए

96. हिंदू, मुसलमान या ब्राह्म के प्रबंधक द्वारा

मृत्यु की तिथि

बौद्ध धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती वर्ष

या हटाने के लिए

नियुक्ति की तारीख

चल के कब्जे की वसूली करने के लिए या

में निहित अचल संपत्ति

आदमी के रूप में वादी

दान जो एक द्वारा हस्तांतरित किया गया है

दान, डब्ल्यू. एच.

बाद में "।

एक मूल्यवान के लिए पिछले प्रबंधक

विचार करें।

साबीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

19. दोनों अनुच्छेदों के बीच के अंतर को टी. कलियमूर्ति और एक अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले द्वारा नोट किया गया है। पाँच गोरी

थाईकल वक्फ और अन्य। यह नीचे लिखा है:

... हमने दो अनुच्छेदों को ध्यान से नोट किया है। , लेख

" 35 .

96 सीमा अधिनियम, 1963 और सीमा के अनुच्छेद 134 बी

अधिनियम, 1908 और हम पाते हैं कि वे एक दूसरे से अलग हैं

जहाँ तक 1908 के अधिनियम के तहत 12 साल से चलना था 1963 के अधिनियम के तहत अंतरणकर्ता की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन, 12 वर्षों की उक्त अवधि मृत्यु, त्यागपत्र या अंतरणकर्ता को हटाने की तारीख, या दान के प्रबंधक के रूप में वादी की नियुक्ति की तारीख, जो भी हो, से चलनी थी।

बाद में "।

20. जहाँ तक पहली बिक्री का संबंध है, बिक्री मुतवल्ली या वक्फ के प्रबंधक द्वारा प्रभावित नहीं की गई थी। बिक्री इसके द्वारा की गई थी मुतवल्ली का भाई। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि अनुच्छेद 96 अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आएगा।

21. जहाँ तक दूसरी बिक्री की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं था,

(समेकन) दिनांक 20.09.1969 के आदेश द्वारा संशोधन को खारिज करने के साथ-साथ दिनांक 02.03.1972 के पहले बहाली आवेदन को भी खारिज करना। यदि उक्त बिक्री वैध पाई जाती है, तो जाहिर है, अपीलार्थी असफल होंगे। यदि दूसरी ओर, बिक्री अमान्य है, तो सवाल यह होगा कि क्या बिक्री की तारीख से 12 साल से आगे शुरू की गई कार्यवाही समय के भीतर होगी। यदि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 96 के तहत शरण लेने से, सीमा की अवधि मुतवल्ली के इस्तीफे की तारीख से शुरू होनी है, तो 12 साल की अवधि 01.05.1988 से शुरू नहीं होगी जब मुतवल्ली कासिम अली खान थे।

इस्तीफा दे दिया? फिर, 12 साल की अवधि केवल वर्ष 2000 में समाप्त होगी। क्या यह नहीं कहा जा सकता था कि कार्रवाई पर रोक नहीं थी? यह यहाँ है कि उच्च न्यायालय का कारण है कि अनुच्छेद 96 एक शून्य बिक्री पर लागू होने के लिए नहीं है। इसके बजाय, यह एक अमान्य बिक्री पर लागू होता है।

22. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वक्फ संपत्ति हो सकती है

प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण की विषय वस्तु (आकाशवाणी देखें)

18 (2008) 9 एस. सी. सी. 206 [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीसी 116)। कि एक मुतवल्ली हालांकि अधिकार हासिल नहीं कर सकता है

प्रतिकूल अधिकार द्वारा संपत्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। (आकाशवाणी देखें

एससी 713)।

23. उच्च न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 96 लागू नहीं होगा क्योंकि यह एक अमान्य बिक्री है और अमान्य बिक्री नहीं है। तर्क इस पर आधारित है

में उड़ीसा के उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रस्तुत किया गया

तमानी साहू (एल. आर. द्वारा मृत) और अन्य बनाम। आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, उड़ीसा और अन्य "। मेंमामला, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के साथ काम कर रहा था

विंग तथ्य:

एक मठ के महांत ने कुछ स्थायी पट्टों को निष्पादित किया। यह आयुक्त की मंजूरी के बिना था जैसा कि इसमें विचार किया गया था। उड़ीसा हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम, 1939 की धारा 58। इस तरह के पट्टे

उपरोक्त प्रावधान के विपरीत थे। महांत को बाद में बर्खास्त कर दिया गया। आयुक्त द्वारा नियुक्त मठ के कार्यकारी अधिकारी ने कब्जे की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 68 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसकी अनुमति दी गई थी। उन्होंने अधिनियम की धारा 25 के तहत कब्जे की वसूली के लिए भी कार्यवाही शुरू की। आयुक्त ने धारा 25 के तहत कार्यवाही की अनुमति दी और अपीलार्थी को बेदखल करने के लिए कलेक्टर को एक मांग जारी करने का निर्देश दिया, जिसने घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया जिसमें तर्क दिया गया था कि उसने निर्बाध कब्जे से किरायेदारी का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त कर लिया था और निषेधाज्ञा की मांग की थी। हम निम्नलिखित निष्कर्ष देख सकते हैं:

" 8. विवाद में मुख्य प्रश्न सीमा और प्रतिकूल कब्जे के संबंध में है। तथ्य का निष्कर्ष यह है कि वादी पट्टे की संबंधित तिथियों, अर्थात् 26-7-1943, 8-1-1944 और 15-7 1944 से भूमि के कब्जे में था। उड़ीसा हिंदू की धारा 25 के तहत कार्यवाही धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 को 30-10-69 पर अनुमति दी गई थी और कब्जा देने के लिए कलेक्टर को निर्देश जारी किया गया था। वादी को बेदखल करने का अधिकार 12 साल की समाप्ति के बाद सीमा द्वारा वर्जित होगा जो 1956 में आता है यदि प्रारंभिक बिंदु संबंधित पट्टों की तारीखें होंगी। यदि, तथापि, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वादी का प्रतिकूल कब्जा महांत की बर्खास्तगी के बाद ही शुरू होगा, तो वसूली का अधिकार

1983 उड़ीसा 205 अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

1969 में समय पर होगा। उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि लागू करने के लिए सही अनुच्छेद का अनुच्छेद 96 है।

नया सीमा अधिनियम। दूसरी ओर, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि नए सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 शासी अनुच्छेद है। किसी भी कला की प्रयोज्यता। 65 या कला। 96 यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हस्तांतरण शुरुआत से ही शून्य था या केवल शून्य था।

XXX

XX

X

XXX

10. एक वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन में किया गया अलगाव

जो जनहित में अधिनियमित किया गया है वह अमान्य है। मान लीजिए कि

स्थायी पट्टे धारा 58 (1) के उल्लंघन में दिए गए थे जो पूर्व मंजूरी के बिना पांच साल से अधिक के लिए पट्टे के अनुदान को प्रतिबंधित करता है। इसलिए स्थायी पट्टों द्वारा हस्तांतरण अमान्य है। हम इस न्यायालय के पहले के फैसलों से इस दृष्टिकोण में मजबूत हैं। नब किशोर पांडा बनाम के मामले में। ऊपर निर्दिष्ट बुलेंद्र, (1974-40 कट एल. टी. 1152), माननीय एस. के. रे, जे. (जैसा कि वे उस समय थे) ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 58 (1) के अनिवार्य प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में बनाया गया एक स्थायी पट्टा शून्य है। अर्जुन के मामले में एकल पीठ के बाद के फैसले में

जेना वी। चैतन्य ठाकुर (1978) 45 कट एल. टी. 461, माननीय बी. के. रे, जे. ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पुराने अधिनियम की धारा 58 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया पट्टा अमान्य है। इस प्रस्ताव के लिए, उनके नेतृत्व ने पहले की एक खंड पीठ पर भरोसा किया

श्री चिरंजीलाल के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

पटवार वी. कॉम. , हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, उड़ीसा, भुवनेश्वर (1974) 40 कट एल. टी. 41। गुलाम अली साहा बनाम के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य एकल पीठ के फैसले में। सुल्तान खान (1966) 32 कट एल. टी. 510: (ए. आई. आर. 1967 उड़ीसा 55), माननीय जी. के. मिश्रा, जे. (जैसा कि वे तब थे) द्वारा निर्णय लिया गया, न्यायालय की अनुमति के बिना वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण की वैधता का सवाल विचार के लिए आया और यह माना गया कि अलगाव, भले ही विचार के लिए हो, शुरू से ही अमान्य था। मस्जिद शाहिद गंज बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए इसे आगे आयोजित किया गया था। एस. जी. पी. समिति, अमृतसर, ए. आई. आर. 1940 पी. सी. 116 ने कहा कि पुराने सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 144 प्रतिकूल रूप से स्वामित्व के अधिग्रहण के ऐसे मामले पर लागू होता है।

अधिकार। इस न्यायालय के दूसरे मामले में एक अप्रकाशित निर्णय में

1966 की अपील सं. 361 का निपटारा 3 अगस्त, 1970 [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(सांबरी बेवा बनाम। उड़ीसा वक्फ बोर्ड) माननीय आर. एन.

मिश्रा, जे. (जैसा कि उन्हें तब माना जाता था) को अलगाव की वैधता माना जाता था।

धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में एक मुतवल्ली द्वारा किया गया

वक्फ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर यह मंजूरी दी जाती है
initio शून्य (पैरा देखें। 8) "।

6. इसके बाद, अदालत ने एक सवाल उठाया कि क्या यह था

अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 96, जो लागू होता है। इसके बाद अदालत ने कहा:

" 12. यह लेख मूल्यवान के लिए हस्तांतरण को संदर्भित करता है।

विचार करें। एक स्थानांतरण जो शून्य है एब इनिशियो की नजर में है

कानून कोई हस्तांतरण बिल्कुल नहीं है और इसलिए इसके दायरे में नहीं आएगा यह लेख। यह
अनुच्छेद स्पष्ट रूप से उन मामलों पर लागू होता है जहाँ

स्थानांतरण से बचा जा सकता है या अमान्य किया जा सकता है। लेकिन अगर स्थानांतरण अमान्य है

अब शुरुआत से फिर कला। 65 नया सीमा अधिनियम लागू होगा। द. हस्तांतरण की तारीख से
हस्तांतरणकर्ता का कब्जा हो जाता है

संपत्ति के संबंध में उनका कोई अधिकार नहीं था और वे केवल एक व्यक्ति थे अतिक्रमणकारी।

XXX

XXX

XXX

14. ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 859 (श्रीनिवास रेड्डी बनाम। एन.

कि हस्तांतरित संपत्ति धार्मिक बंदोबस्ती की है और जो उसके द्वारा इस आधार पर बनाए गए थे
कि उक्त संपत्ति उसकी है।

अपनी निजी संपत्ति? " उनके अधिपतियों का मानना था कि अनुच्छेद 134-बी इस तरह के
भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यह माना गया था कि चरित्र

पूर्व प्रबंधक द्वारा किए गए अभ्यावेदन के संबंध में

यह अनुच्छेद अमान्य या अमान्य लेनदेन पर लागू होता है जिसके लिए उत्पन्न नहीं हुआ था उस मामले में विचार करें। "

(जोर दिया गया)

25. चूंकि ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 859 और उसी का संदर्भ दिया गया था।

विशिष्ट रूप से, हम उक्त निर्णय का विज्ञापन कर सकते हैं। विवाद,

इस न्यायालय के समक्ष यह लिया गया था कि जब द्वारा स्थानांतरण किया जाता है

नागर प्रबंधक के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, इस तरह का स्थानांतरण शून्य है साबीर अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रारंभ में, हस्तांतरण की तारीख से हस्तांतरणकर्ता का कब्जा प्रतिकूल था और इसलिए, ऐसी स्थिति में, सीमा अधिनियम, 1908 का अनुच्छेद 134 बी, वर्तमान सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 96 का पूर्ववर्ती अनुच्छेद, तीसरे कॉलम में हमने जो अंतर नोट किया है, वह लागू नहीं होगा। इस न्यायालय ने, वास्तव में, उल्लेख किया कि प्रिवी काउंसिल के दो निर्णय, अर्थात्, 1900 27 इंडियन अपील 69 (ईसी) और 37 इंडियन अपील 147 ईसी ने उक्त तर्क का समर्थन किया। पहले मामलों (27 भारतीय अपील 69 ई. सी.) के संबंध में, यह पाया गया है कि प्रिवी काउंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां किसी धार्मिक बंदोबस्ती के वंशानुगत न्यासियों ने प्रबंधन के अपने वंशानुगत अधिकार को बेच दिया और दान की गई संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया, तो बिक्री अमान्य थी, यदि कोई प्रथा अन्यथा प्रदान नहीं करती थी। यह भी उल्लेख किया गया कि प्रिवी काउंसिल सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 124 के मामले को देख रही थी। यह आगे पाया गया कि जो बेचा गया वह वंशानुगत कार्यालय था और साथ ही संपत्ति भी अचल थी।

मंदिर की संपत्तियां भी बेची गईं। आगे तर्क यह था कि यह पुराने अधिनियम का अनुच्छेद 144 था जो 12 साल के प्रतिकूल कब्जे के बाद मुकदमे को रोकने के लिए काम करता था। न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में कुछ मतभेदों को नोट किया। इसने आगे संदेह व्यक्त किया कि क्या निर्णय 27 भारतीय अपील 69 (ई. सी.) में से पहला यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि यदि संपत्ति का एक हिस्सा किसी धार्मिक निधि के प्रबंधक द्वारा इस आधार पर हस्तांतरित किया गया था कि वह उसका है, तो उत्तराधिकारी प्रबंधक का अधिकार खो सकता है। इसके बाद, न्यायालय ने पाया कि इस मामले को सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 134 बी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने पाया कि इससे अनुच्छेद 134 बी के आवेदन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि हस्तांतरण इस आधार पर किया जाता है कि संपत्ति बंदोबस्ती की नहीं बल्कि प्रबंधक की है। उत्तराधिकारी प्रबंधक के लिए जो कुछ भी साबित करना आवश्यक था, वह निम्नलिखित तथ्य पाए गए:

" (1) कि संपत्ति धार्मिक निधि की है; (2) कि यह पिछले प्रबंधक द्वारा हस्तांतरित की गई थी; और (3) कि हस्तांतरण

यह एक मूल्यवान विचार के लिए था। का चरित्र

संपत्ति, जो हस्तांतरण का विषय है, के साथ अपने संबंध के संबंध में पूर्व प्रबंधक द्वारा किए गए अभ्यावेदन कला के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक हैं। 134 - बी. "

26. उड़ीसा का उच्च न्यायालय चिंतामणि साहू (एल. आर. द्वारा मृत) (उपरोक्त) मामले में उपरोक्त निर्णय को इस आधार पर अलग करता है कि यह न्यायालय इस सवाल पर विचार नहीं कर रहा था कि क्या अनुच्छेद 134 बी अमान्य या अमान्य लेनदेन पर लागू होता है क्योंकि यह उत्पन्न नहीं हुआ था।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि वे एक अलग सिद्धांत निर्धारित करते हैं। ना जीयंगर मठ में, तिरुपत बनाम। सी. वी. पुरुषोत्तम और अन्य 20,

एकल न्यायाधीश ने अनुच्छेद 134 ए, अनुच्छेद 134 बी के इतिहास का पता लगाया,

134 सी कानून की तीसरी रिपोर्ट के संदर्भ में भी

भारत का मिशन। उक्त भाग इस प्रकार है:

" 12. विधि आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में कहा कि

" अनुच्छेद 134-बी द्वारा कवर किए गए मुकदमों के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु मृत्यु, इस्तीफे या हस्तांतरणकर्ता को हटाने की तारीख है। इसने कुछ मामलों में कुछ कठिनाइयों को जन्म दिया है। इस प्रकार, एक बंदोबस्ती आयुक्त को दशकों के बाद पिछले प्रबंधकों में से एक द्वारा अलगाव को चुनौती देना आवश्यक लग सकता है; या, मृत्यु, त्यागपत्र या एक प्रबंधक को हटाने और उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बीच 12 साल से अधिक का अंतराल हो सकता है। ऐसे मामलों में, प्रबंधक के रूप में वादी की नियुक्ति की तारीख को सीमा के लिए प्रारंभिक बिंदु बनाना अधिक न्यायसंगत होगा। लेकिन ऐसे मामले और परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ मौजूदा प्रावधान संस्था के लिए अधिक अनुकूल हो सकता है।

दोनों आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान करने के लिए, दोनों तिथियों में से बाद में

सीमा के प्रारंभिक बिंदु के रूप में लिया जाए।

28. न्यायालय ने उद्देश्यों और कारणों के कथन पर भी भरोसा किया। ओ श्रीनिवास (सुप्रा) को संदर्भित करता है। इसके अलावा, न्यायालय ने संशोधन से पहले कानून में ओशन निर्धारित किया, जो इस प्रकार है:

" 23. उपरोक्त चर्चा से कानून की निम्नलिखित स्थिति सामने आती है। मठ का एक महान्त अपने जीवनकाल से आगे के लिए मठ की संपत्ति के संबंध में कोई रुचि पैदा करने में अक्षम होता है। वह कर सकता है।

अपने उत्तराधिकारी के कहने पर अमान्य। सवाल करने का अधिकार उत्तराधिकारी को अलगाव केवल विदेशी की मृत्यु पर ही प्राप्त होता है। विदेशी का प्रतिकूल अधिकार भी उसकी मृत्यु की तारीख से ही चलने लगता है और तब तक नहीं। मंदिर की भूमि का स्थायी पट्टा भी इस प्रकृति का अलगाव है। यदि यह कानूनी आवश्यकता या लाभ के लिए नहीं था तो यह मठ पर बाध्यकारी नहीं है। इसका कारण

1974 एपी 175 बीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

कार्रवाई जो एक बार अर्जित होने के बाद जारी रहती है। मठ का अधिकार

सीमा कानून द्वारा निर्धारित अवधि के अंत में उस संपत्ति के संबंध में बुझा दिया जाएगा। प्रत्येक उत्तराधिकारी महांत को अपने पक्ष में कार्रवाई के कारण का पुनरुत्थान नहीं मिलता है। कानून के तहत, जैसा कि 1963 से पहले था, उत्तराधिकारी की नियुक्ति को कभी भी सीमा की नई शुरुआत देने के लिए नहीं माना गया था। यह कानूनी आवश्यकता के लिए किया गया अलगाव था या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एक सवाल था।

29. इसके बाद, विद्वान न्यायाधीश ने अनुच्छेद 134 बी के सही अर्थ को उजागर किया:

" 24. 1963 में जब सीमा अधिनियम में संशोधन किया गया तो कानून की स्थिति ऐसी थी। विधायिका को मौजूदा कानून और अदालतों द्वारा उस समय लागू कानून को दी गई व्याख्या के बारे में पता होना चाहिए। यदि किसी हिंदू या मुसलमान धार्मिक या धर्मार्थ दान के संबंध में अमान्य अलगाव पर सवाल उठाने का अधिकार किसी मठ या धार्मिक संस्थान को नहीं दिया जाता है, तो ऐसी संस्था हमेशा के लिए संपत्तियों को खो देती है। चूंकि राज्य ऐसी संस्थाओं की संपत्तियों की रक्षा और सुरक्षा में रुचि रखता था, इसलिए इसने ऐसा किया

1963 में उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संशोधन। कानून.

आयोग, जिसे उस प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था

सुझाव दिया कि हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धार्मिक या धर्मार्थ दान के मामले में, ऐसे अलगावों को दरकिनार करने के लिए उत्तराधिकारी महांत द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए एक नई शुरुआत या एक समाप्ति दी जानी चाहिए, जो कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं किए गए थे।

या संस्था का लाभ। विधानमंडल ने भी उस दृष्टिकोण को स्वीकार किया और अनुच्छेद 96 के कॉलम 3 में डाला, जिसमें पहले केवल निम्नलिखित शब्द थे: स्थानान्तरणकर्ता की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन "निम्नलिखित शब्द:" या बंदोबस्ती के प्रबंधक के रूप में वादी की नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो। संशोधन के स्पष्ट शब्दों से यह स्पष्ट है कि

विधायिका ने ऐसे अलगावों को ध्यान में रखा था जिनके बारे में मुकदमे दायर करने का अधिकार पहले से ही वर्जित हो गया है और इसलिए वह उनके संबंध में सीमा की एक नई अवधि प्रदान करना चाहती है। विधानमंडल इस तथ्य से भी अवगत था कि 1963 से पहले के निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, एक बंदोबस्ती द्वारा प्रबंधक के रूप में वादी की नियुक्ति की तारीख ने उसे उस उद्देश्य के लिए सीमा की नई शुरुआत नहीं दी। यह केवल उपचार के लिए था इस तरह के कानून की व्याख्या में महसूस की गई स्पष्ट कठिनाइयाँ [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधन, यदि वादी को मुकदमा दायर करने की तारीख से 12 साल के भीतर नियुक्त किया गया था, तो वह किसी भी अलगाव पर सवाल उठा सकता है, जो पिछले प्रबंधक द्वारा कानूनी आवश्यकता या मठ के लाभ के लिए नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि मृत्यु की तारीख से 12 साल बीत चुके हैं, स्थानांतरणकर्ता प्रबंधक का इस्तीफा या निष्कासन वादी के रास्ते में इस तरह के मुकदमे में खड़ा नहीं होगा। संपत्ति की वापसी। अंतिम तीन शब्दों से यह स्पष्ट है।

संशोधन 'जो भी बाद में हो', जानबूझकर विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए अदालतों को हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती के किसी भी प्रबंधक द्वारा किसी बंदोबस्ती की चल या अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए की गई किसी भी कार्रवाई पर कानून के सादे शब्दों को लागू करना होगा, जो किसी पूर्व प्रबंधक द्वारा मूल्यवान विचार के लिए अलगाव का विषय था। यह भी स्पष्ट है कि हस्तांतरणकर्ता प्रबंधक को वादी का तत्काल पूर्ववर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, जो ऐसा मुकदमा दायर करता है। अनुच्छेद 96 के अध्ययन से इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। यह पर्याप्त है यदि अलगाव पिछले प्रबंधक द्वारा किया गया था। पहला कॉलम नहीं कहता है

कि यह पिछले प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए।

30. राज्य वक्फ बोर्ड, मद्रास में, द्वारा प्रतिस्थापित

G.O.Ms में तमिलनाडु का उल्लेख। सं. 2031, दिनांक 20 नवंबर, और G.O.Ms द्वारा नियुक्त। सं. 2264, दिनांक 30 दिसंबर, 1967, वक्फ मद्रास के लिए विशेष अधिकारी बनाम। सुब्रमण्यम और अन्य 2 1, न्यायाधीश, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर रहे थे:

कथित रूप से संपत्तियों की वसूली के लिए मुकदमे दायर किए गए थे

वक्फ से संबंधित हैं, जिन्हें इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि

सीमा। न्यायालय ने अनुच्छेद 96 के तीसरे कॉलम के बाद के भाग पर ध्यान आकर्षित किया और पाया कि मुकदमा समय के भीतर था। उक्त मामले में, वास्तव में, वक्फ बोर्ड वादी था। एकल न्यायाधीश ने पाया कि वक्फ बोर्ड का गठन केवल वर्ष 1953 में किया गया था। सूट 1967 में स्थापित किए गए थे। अनुच्छेद 96 के तीसरे कॉलम में 'नियुक्त प्रबंधक' के अर्थ के भीतर बोर्ड को प्रबंधक की भूमिका सौंपने में भी, न्यायालय ने समर्थन प्राप्त किया

चिन्ना जीयंगर मठ (ऊपर) में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से। हम निम्नलिखित तर्क देख सकते हैं:

1977 मद्रास 79 बीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 6. विद्वान वकील का तर्क अब यह है कि केवल जब वक्फ बोर्ड वक्फ का प्रत्यक्ष प्रबंधन ग्रहण करता है, तो इसे एक प्रबंधक कहा जा सकता है जैसा कि कला के तीसरे स्तंभ में विचार किया गया है। 96 नए अधिनियम और जब तक प्रत्यक्ष प्रबंधन की कोई धारणा नहीं है, तब तक वक्फ बोर्ड को प्रबंधक नहीं कहा जा सकता है। मैं एक दृष्टिकोण से इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। न तो वक्फ अधिनियम की धारा 42 और न ही धारा 43-ए, जिस पर निर्भरता रखी गई है, "प्रबंधक" शब्द का उपयोग करती है। धार्मिक या धर्मार्थ दान के संबंध में "प्रबंधक" शब्द का अर्थ यह नहीं है कि

कला। उक्त शब्द उस व्यक्ति को दर्शाता है जो बंदोबस्ती के प्रशासन का प्रभारी है या संपत्ति का प्रबंधन करता है या दान के प्रदर्शन की निगरानी करता है और यह शब्द बहुत व्यापक और सामान्य महत्व का है। वास्तव में, न्यायमूर्ति नटराजन के निर्णय में वक्फ अधिनियम की धारा 15 (2) में निहित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वक्फ अधिनियम की धारा 15 (1) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले किसी भी नियम के अधीन,

किसी राज्य में सभी वक्फों का सामान्य पर्यवेक्षण राज्य के लिए स्थापित बोर्ड में निहित होगा और यह बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके पर्यवेक्षण के तहत वक्फों का उचित रूप से रखरखाव किया जाए।

नियंत्रित और प्रशासित और इसकी आय विधिवत उन उद्देश्यों पर और उन उद्देश्यों के लिए लागू की जाती है जिनके लिए ऐसे वक्फ थे। बनाया या इरादा किया गया। उप-एस। (2) या धारा 15, उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

दृष्टांत में, कुछ निर्दिष्ट शक्तियों की भी गणना की गई है। इस प्रकार गणना की गई एक ऐसी निर्दिष्ट शक्ति धारा 15 (2) (एच) में निहित है, जो वक्फ बोर्ड को खोए हुए धन की वसूली के लिए उपाय करने में सक्षम बनाती है।

किसी भी वक्फ के गुण। धारा 15 (2) (i) वक्फ बोर्ड को भी सक्षम बनाती है। वक्फ अधिनियम की धारा 15 (1) और 15 (2) का संयुक्त प्रभाव निश्चित रूप से वक्फ को नामित करने के लिए पर्याप्त होगा।

वक्फ संपत्ति के कब्जे की वसूली के उद्देश्य से एक प्रबंधक के रूप में बोर्ड और इसके परिणामस्वरूप इसे निश्चित रूप से कला के तीसरे कॉलम द्वारा विचारित "प्रबंधक" कहा जा सकता है। 96 में से

नया सीमा अधिनियम और यदि ऐसा माना जाता है, तो कानून के तहत वक्फ बोर्ड के गठन को निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड की वक्फ के प्रबंधक के रूप में नियुक्ति माना जा सकता है, क्योंकि शब्द "नियुक्ति" भी शब्द "प्रबंधक" की तरह ही एक कला शब्द नहीं है और इसलिए इसे प्राप्त करना पड़ता है।

सामान्य, प्राकृतिक और सामान्य अर्थ। "

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. इससे पहले कि हम अंत में इस सवाल पर घोषणा करें कि क्या अनुच्छेद 96 एक अमान्य लेनदेन के संबंध में लागू होगा, हम इसे मानते हैं।

कुछ अन्य पहलुओं से निपटने के लिए उपयुक्त। विचाराधीन वक्फ 26.07.1934 पर अकबर अली खान की रचना है। यह अपीलार्थी का मामला है कि इसे वक्फ अल औलाद के रूप में सं. 1476 पर पंजीकृत किया गया था। दूसरे बिक्री विलेख का हस्तांतरणकर्ता, अर्थात्, कासिम अली खान ने मुतवल्ली के रूप में पदभार संभाला जब उनके पिता अकबर अली खान की मृत्यु हो गई। यह विवाद में नहीं है कि कासिम अली खान ने 1950 के ओएस 1 की स्थापना की थी जिसमें उन्होंने अपने पिता अकबर अली खान और वक्फ संपत्ति के एक हिस्से के हस्तांतरणकर्ता को शामिल किया था, जिसे उनके पिता ने प्रभावित किया था। का फरमान वादी के पक्ष में विचारण न्यायालय की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.1962 के निर्णय द्वारा की गई थी। निर्णय ने निचली अदालत के इस विचार की पुष्टि की कि एक वैध वक्फ था। उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि मुस्लिम कानून के तहत एक शिया द्वारा वक्फ के निर्माण के संबंध में सभी कानूनी आवश्यकताओं को तैयार किया गया था। यह माना गया था कि अकबर अली खान ने 26.07.1934 पर एक वक्फ-अलाल-औलाद बनाया था जो कानून में प्रभावी था। इसलिए, जैसा कि वक्फ जो पहले मुतवल्ली भी थे, और उनके बेटे कासिम अली खान के बीच, उच्च न्यायालय के फैसले में निष्कर्ष स्पष्ट रूप से मानते हैं कि एक वैध वक्फ था। अकबर अली खान की मृत्यु के बाद, उनके बेटे कासिम अली खान ने मुतवल्ली के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने 1959 में ओएस 421 की स्थापना की। इसमें, उनके भाई प्रतिवादी थे, अर्थात्, कासिम अली खान और रजा अली खान। यह प्रतिवादियों का राजस्व अभिलेखों में अपने नाम बदलने का कार्य था, जिसके कारण उक्त मुकदमा दायर किया गया। यह मुकदमे के लंबित होने के दौरान है, यानी, प्रतिवादियों में से एक काज़िम अली खान ने हमारे सामने एक अपील में पहले प्रतिवादी के पक्ष में अपना कथित, एक-तिहाई अधिकार स्थानांतरित कर दिया। मुकदमा तय किया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील में, 25.09.1963 दिनांकित आदेश द्वारा मामले को वापस भेज दिया। हालाँकि, जब यह ऐसा था, तब यू. पी. कार्यवाही समेकन अधिनियम, 1953 के तहत समेकन कार्यवाही शुरू हुई। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत, समेकन शुरू होने पर मुकदमे की कार्यवाही कम हो जाएगी। इसके बाद, यह समेकन अधिकारी होता है, जिसका निर्णय निपटान अधिकारी के समक्ष अपील योग्य होता है और जिसके बाद के प्राधिकरण के निर्णय को उप निदेशक द्वारा संशोधन में संशोधित किया जा सकता है, जिसका नियंत्रण होता है। मुकदमे में वादी, अर्थात्, तदनुसार, कासिम अली खान ने अपने भाइयों के नाम दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई। कासिम अली खान की आपत्तियों को योग्यता के साथ पाया गया। परिणामस्वरूप, भाइयों के नाम हटाने का निर्देश दिया गया और

उनके स्थान पर वक्फ का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

भाई सबीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

कासिम अली खान ने समझौते के समक्ष असफल अपील की अधिकारी। उप निदेशक के सामने उनके द्वारा किया गया एक संशोधन साबित हुआ

समान रूप से असफल क्योंकि इसे 29.01.1969 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। आदेश योग्यता के आधार पर पारित किया गया था। इसमें लिखा है, अन्य बातों के साथ:

" 3. कि मैं पाता हूँ कि वक्फ को पक्षों के बीच प्रवेश दिया जाता है। विवादित जमीन सर की थी। वक्फ के निष्पादन के बाद, सर को पूर्व-स्वामित्व किरायेदारी में परिवर्तित किया जाना चाहिए था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि पूर्व-स्वामी किरायेदारी के अधिकार, जो अंततः निहित होने की तारीख के ठीक बाद सरदारी में परिवर्तित हो गए थे, वक्फ से संबंधित नहीं थे और फिर आवेदकों को उनके पिता के उत्तराधिकारी के रूप में जारी रखने का औचित्य था। लेकिन, स्थिति दूसरी है, जब वक्फ में बनाए गए पक्षों के पिता, विवादित भूमि जो सर थी, को अभिग्रहण किरायेदारी में परिवर्तित नहीं किया गया था और निहित होने की तारीख के बाद भूंडरी दर्ज किया गया था। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि भूमि में पूर्ण अधिकार सर्वशक्तिमान और उचित मार्ग को हस्तांतरित किए गए थे। विपक्ष को रिकॉर्ड करना था। मुतवल्ली के रूप में पार्टी करें और आवेदकों के नाम हटा दें। नियमित अदालतों में मुकदमेबाजी में, दीवानी अदालत ने भी यही विचार रखा था, लेकिन इन अदालतों में मामला अंतिम नहीं हो सका। समेकन के आगमन के कारण। इन परिस्थितियों में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि

निचली अदालतें मजबूत हैं और हस्तक्षेप के लायक नहीं हैं।

32. प्रतिवादी, अर्थात्, कासिम अली खान और रजा अली खान ने पुनर्स्थापना आवेदन दायर किया जिसे दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

02.03.1972 . एक और पुनर्स्थापना आवेदन दायर किया गया था। यही कारण है कि कासिम अली खान, कासिम अली खान और रजा अली खान, तीनों भाइयों के बीच 13.02.1974 पर समझौता किया गया था। उन्होंने वक्फ को अस्वीकार करने का इरादा किया। उन्होंने घोषणा की कि यह नहीं था प्रभावी हुआ। यह इस समझौते के आधार पर था कि दूसरे बहाली आवेदन की अनुमति दी गई थी। संशोधन और पुनर्स्थापना को खारिज करने वाले पहले के आदेशों को उप निदेशक द्वारा रद्द कर दिया गया था। दिनांकित 13.02.1974 समझौता उसी का आधार बना। यह उक्त समझौते पर कार्यवाई कर रहा है और उस पर पारित आदेश है कि कासिम अली खान ने कथित तौर पर अपना एक तिहाई हिस्सा अपने भतीजे को दिनांकित 12.09.1974 के बिक्री विलेख द्वारा पहुँचाया था।

33. 1960 का अधिनियम लागू था। अधिनियम की धारा 69 के रूप में प्रावधान किया गया है

निम्नलिखित है:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वक्फ संपत्ति या अधिकारों के स्वामित्व से संबंधित वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही लंबित नहीं है। बोर्ड की मंजूरी के बिना मुतवालियों के साथ समझौता किया जाएगा।

34. इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 49 ए और 49 बी निम्नानुसार है:

" 49 वक्फ की अचल संपत्ति का हस्तांतरण-विलेख या लिखत, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वक्फ बनाया गया है, में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इसके माध्यम से कोई हस्तांतरण नहीं

((i) बिक्री, उपहार, बंधक या विनिमय; या ((ii) तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टा

कृषि भूमि, या गैर-कृषि और वक्फ की किसी भी अचल संपत्ति के निर्माण के मामले में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना वैध होगी। 49 - बी. धारा 49-ए के उल्लंघन में हस्तांतरित वक्फ संपत्ति की वसूली। - (1) यदि बोर्ड को इस तरह से जांच करने के बाद संतुष्ट किया जाता है कि धारा 30 के तहत रखे गए वक्फ रजिस्टर में वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज की गई कोई भी अचल संपत्ति, धारा 49-ए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना स्थानांतरित कर दी गई है, तो वह उस कलेक्टर को एक अनुरोध भेज सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति संपत्ति प्राप्त करने और उसे देने के लिए स्थित है।

(2) उप-धारा (1) के तहत मांग की प्राप्ति पर, कलेक्टर एक आदेश पारित करेगा जिसमें संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति को आदेश की सेवा की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर बोर्ड को संपत्ति देने का निर्देश दिया जाएगा।

(3) उप-धारा (2) के तहत पारित प्रत्येक आदेश की तामील की जाएगी। (क) इसे देकर या निविदा देकर या डाक द्वारा उस व्यक्ति को भेजकर जिसके लिए यह इरादा है; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो इसे किसी पर चिपकाकर

उनके अंतिम ज्ञात व्यवसाय का विशिष्ट हिस्सा, या इसे अपने परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या नौकर को देकर या उसे सौंपकर या संपत्ति के किसी विशिष्ट हिस्से पर चिपकाकर, जिससे यह संबंधित है:

साबीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(4) उप-क्लेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा (2) आदेश की सेवा की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, जिले के न्यायालय में अपील कर सकती है।

(5) जिला न्यायाधीश या तो स्वयं अपील का निपटारा कर सकता है या इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किसी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है और ऐसी किसी भी अपील को वापस ले सकता है और या तो उसका निपटारा कर सकता है या इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, और प्रत्येक मामले में न्यायालय अंतिम होगा।

(6) जहां उप-धारा (2) के तहत पारित किसी आदेश का पालन नहीं किया गया है और ऐसे आदेश के खिलाफ अपील करने का समय समाप्त हो गया है और उस समय के भीतर कोई अपील या अपील, यदि कोई हो, खारिज कर दी गई है, तो क्लेक्टर उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करेगा जिसके संबंध में -

आदेश दिया गया है, ऐसे बल का उपयोग करते हुए जो आवश्यक हो सकता है, क्योंकि उद्देश्य, और फिर इसे बोर्ड को वितरित करें।

(7) इस धारा के तहत अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए क्लेक्टर

ऐसे नियमों द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो उस ओर से बनाए जा सकते हैं

राज्य सरकार "।

35. धारा 49 ए और 49 बी को 1960 के अधिनियम में शामिल किया गया था।

1971 का यू. पी. अधिनियम 28। इसलिए, कासिम अली खान द्वारा अपने भतीजे के पक्ष में दिनांकित बिक्री विलेख, जो बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना बिक्री के खिलाफ निषेध के दायरे में था, अवैध था। यह वह कथा है जो इस सवाल को जन्म देती है कि

क्या बिक्री अमान्य है क्योंकि यह एक वैधानिक अधिदेश का उल्लंघन था। यदि यह ऐसे कारण से शून्य है, तो क्या यह हस्तांतरणकर्ता द्वारा प्रतिकूल कब्जे की अवधि की शुरुआत और संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्या यह सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 को लागू करने के लिए दरवाजे नहीं खोलेगा? तो क्या यह समान रूप से सीमा अधिनियम की धारा 27 को अपने दरवाजे पर नहीं लाएगा? परिणामस्वरूप, 13.09.1974 से 12 वर्ष की समाप्ति पर, क्या अपीलार्थी द्वारा स्थापित शीर्षक समाप्त हो जाएगा? यदि ऐसा है, तो क्या अधिनियम के [2023] 6 एस. सी. आर. में आने के बाद वर्ष 1997 में दायर की गई शिकायत नहीं होगी?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

01.01.1996 पर बल लगाना, जिससे अधिनियम की धारा 52 के तहत शक्ति का उपयोग किया जा सके, अस्वीकार्य होगा?

36. अधिनियम की धारा 52, जो वक्फ बोर्ड के नियंत्रक और कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई का स्रोत है, की अगली कड़ी है। धारा 51। धारा 51 (1), अन्य बातों के साथ-साथ, 2013 के अधिनियम 27 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले, निम्नानुसार पढ़ा गया था:

" 51 (1) वक्फ विलेख में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी अचल संपत्ति का कोई भी उपहार, बिक्री, विनिमय या बंधक जो वक्फ संपत्ति है, अमान्य होगा, जब तक कि ऐसा उपहार, बिक्री, विनिमय या बंधक बोर्ड की पूर्व मंजूरी से प्रभावित न हो जाए: बशर्ते कि किसी भी मस्जिद, दरगाह या खंगाह को उपहार में नहीं दिया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा या गिरवी नहीं रखा जाएगा, सिवाय उस समय लागू किसी कानून के।

37. हम केवल यह देख सकते हैं कि 2013 के अधिनियम 27 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 51 (1) (ए), प्रावधानों के अधीन, बिक्री, उपहार, विनिमय या

वक्फ संपत्ति का बंधक या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा। अधिनियम की धारा 52 में प्रावधान है कि यदि बोर्ड संतुष्ट है, तो कोई भी जांच करने के बाद,

जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है कि धारा 36 के तहत रखे गए वक्फ रजिस्टर में दर्ज की गई वक्फ की किसी भी अचल संपत्ति को अधिनियम की धारा 51 या 56 का उल्लंघन करते हुए बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना स्थानांतरित कर दिया गया है, यह उस स्थान के कलेक्टर को एक अनुरोध भेज सकता है जिसके भीतर संपत्ति प्राप्त करने और वितरित करने के लिए स्थित है। अधिकार। कलेक्टर आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर बोर्ड को संपत्ति देने के लिए कब्जे वाले व्यक्ति को निर्देश देने के लिए बाध्य है। इसी प्रावधान के तहत विवादित आदेश पारित किए गए।

38. यह ध्यान दिया जाएगा कि अधिनियम 01.01.1996 पर लागू हुआ। धारा 52 बोर्ड को कलेक्टर को अनुरोध भेजने का अधिकार देती है, यदि -

धारा 51 का उल्लंघन करते हुए बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है। हमने देखा है कि धारा 51 में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना संपत्ति की कोई भी बिक्री, जो वक्फ संपत्ति है, अमान्य होगी। इस मामले में दोनों बिक्री 01.01.1996 से पहले हुई थी। पहली बिक्री दिनांकित 14.10.1960 है जबकि दूसरी बिक्री दिनांकित 13.09.1974 है।

39. अधिनियम की धारा 112 में निरसन और बिक्री का प्रावधान है। वह पढ़ता है

इस प्रकार है:

साबीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 112. रद्द करें और बचत करें। — (1) वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 69) इसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, उक्त अधिनियमों के तहत किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी।

(3) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले, किसी भी राज्य में, उस राज्य में लागू है, तो कोई भी कानून जो इसके अनुरूप है -

यह अधिनियम कि संबंधित कानून निरस्त हो जाएगा: बशर्ते कि ऐसा निरसन उस संगत विधि के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा, और उसके अधीन रहते हुए, तत्समान विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई किसी भी चीज़ या की गई किसी भी कार्रवाई को इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया या किया गया समझा जाएगा जैसे कि यह अधिनियम उस दिन लागू था जिस दिन ऐसी चीज़ें लागू थीं।

किया गया या कार्रवाई की गई।

40. 1960 के अधिनियम की धारा 49 बी अधिनियम की धारा 52 के समान है। दूसरे शब्दों में, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि 1960 के अधिनियम की धारा 49 ए का उल्लंघन करते हुए कोई हस्तांतरण किया जाता है, तो बोर्ड कब्जे की वसूली के लिए कलेक्टर को अनुरोध भेज सकता है। 1960 के अधिनियम की धारा 49 ए भी

घोषणा करता है कि निरसन संबंधित कानून के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। इस मामले में संबंधित कानून धारा 49 ए है जिसे धारा 49 बी के साथ पढ़ा जाता है। इसके तहत शक्ति के प्रयोग में की गई कार्रवाई को अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग में की गई कार्रवाई माना जाना चाहिए। अधिनियम के तहत शक्तियों को धारा से प्रवाहित माना जाना चाहिए 52 अधिनियम से। उक्त प्रयोजन के लिए, धारा 112 (3) के परंतुक में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान, जो इस मामले में धारा 52 होंगे, को कानून पुस्तिका में माना जाना चाहिए।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. लेकिन फिर क्या यह कहा जा सकता है कि विचाराधीन स्थानान्तरण के संबंध में 1960 के अधिनियम की धारा 49 बी के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसलिए, अधिनियम की धारा 112 (3) का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है? हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि, शक्ति मौजूद है क्योंकि अनुसरण करने के कारणों के लिए, अपीलार्थी निश्चित आधार पर विफल हो जाएंगे। 42. एक तर्क उठाया गया

है कि विचाराधीन वक्फ-अलाल-औलाद को अधिनियम के तहत वक्फ के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह पहले प्रतिवादी का मामला है कि मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 में वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान नहीं था। यद्यपि मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 अधिनियमित किया गया था, वक्फ-अलाल-औलाद को इसके संचालन से बाहर रखा गया था। न तो 1936 का अधिनियम और न ही 1960 का अधिनियम लागू होता है और अपीलार्थी यह दावा नहीं कर सकता कि वक्फ किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत था। इसका कोई धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य नहीं है। मैं विशिष्ट बहिष्करण को ध्यान में रखते हुए

1936 अधिनियम, यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम वक्फ पर लागू नहीं होता था क्योंकि पूरी आय वक्फ के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए जानी थी।

43. विचाराधीन वक्फ अकबर अली खान द्वारा विलेख द्वारा बनाया गया है।

दिनांकित 26.07.1934। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक वक्फ-अलाल-औलाद है। एक वक्फ-अलाल-औलाद मोहम्मदी कानून के तहत एक वक्फ है। यह प्रिवी काउंसिल थी जिसमें अब्दुल फतह मोहम्मद इशाक बनाम। रुसोमी धर

चौधरी 22 ने कहा कि यदि दान भ्रामक या इतना छोटा है, तो इसे वक्फ के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 पारित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 और 4 इस प्रकार है:

“ 3. मुसलमान धर्म का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वक्फ का निर्माण करना वैध होगा जो अन्य सभी मामलों में मुसलमान कानून के प्रावधानों के अनुसार है।

अन्य उद्देश्य: -

(क) अपने परिवार, बच्चों या वंशजों के पूर्ण या आंशिक रखरखाव और समर्थन के लिए और

(ख) जहां वक्फ बनाने वाला व्यक्ति हनफी मुसलमान है, वह अपने जीवनकाल के दौरान अपने रखरखाव और समर्थन के लिए या संपत्ति के किराए और लाभ से अपने ऋणों के भुगतान के लिए भी है।

समर्पित।

22 22 भारतीय अपील 76 साबीर अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

बशर्ते कि ऐसे मामलों में अंतिम लाभ स्पष्ट रूप से हो

या अप्रत्यक्ष रूप से गरीबों के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए आरक्षित
मुसलमान कानून द्वारा एक धर्म, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त

स्थायी चरित्र का उद्देश्य।

4. ऐसे किसी भी वक्फ को केवल अमान्य नहीं माना जाएगा।

क्योंकि उसमें गरीबों या अन्य धार्मिक लोगों के लिए आरक्षित लाभ,

परिवार, बच्चों या वंशजों के विलुप्त होने के बाद तक
वक्फ बनाने वाला व्यक्ति "।

44. इसके बाद मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 पारित किया गया।

यह पूरे ब्रिटिश भारत पर लागू हुआ। धारा 2 (ई) में निहित वक्फ की परिभाषा इस प्रकार थी:

" 2 (ई) 'वक्फ' का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण।

किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी संपत्ति के मुसलमान धर्म का प्रचार करना

मुसलमान कानून द्वारा धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त,

लेकिन इसमें कोई वक्फ शामिल नहीं है, जैसा कि धारा 3 में वर्णित है
मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913, जिसके तहत कोई भी लाभ

उस समय के लिए जिसके द्वारा वह व्यक्ति अपने लिए दावा कर सकता है

वक्फ का निर्माण उनके परिवार या वंशजों में से किसी ने किया था।

(जोर दिया
गया)

45. 1923 के अधिनियम की धारा 3 ने मुतवल्ली को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया

सक्षम न्यायालय को कुछ विशिष्टताओं वाला विवरण। वक्तव्य की सूचना धारा 4 के तहत प्रकाशित की जानी
थी। 1923 के अधिनियम में खातों के लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया और मुतवल्ली द्वारा किए जा
सकने वाले खर्च का प्रावधान जोड़ा गया। धारा 10 में दंड का प्रावधान किया गया है। कुछ वक्फों को धारा
12 के तहत इसके दायरे से बाहर रखा गया था। संयुक्त प्रांतों में, जिसका अर्थ था आगरा और अवध के संयुक्त
प्रांत, 1936 का अधिनियम अधिनियमित किया गया। इसकी धारा 2 इस प्रकार है:

" 2 (1) जैसा कि इसमें अन्यथा विशेष रूप से कहा गया है, इसे छोड़कर, यह अधिनियम

सभी वक्फों पर लागू होता है, चाहे वे इस अधिनियम के आने से पहले या बाद में बनाए गए हों।
बल में, जिसकी संपत्ति का कोई भी हिस्सा संयुक्त राज्य में स्थित है

(2) यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:
((i) किसी विलेख द्वारा बनाया गया वक्फ, यदि कोई हो, जिसकी शर्तों के तहत नहीं

6 एस. सी. आर. भूमि की कटौती के बाद कुल आय के 75 प्रतिशत से कम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्ति की सरकार को देय राजस्व और उपकर वक्फ के विलेख द्वारा कवर किया गया, यदि कोई हो, तो वक्फ या उसके वंशजों या उसके परिवार के किसी सदस्य के लाभ के लिए कुछ समय के लिए देय है:

((ii) एक वक्फ केवल निम्नलिखित में से किसी एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है:

(क) वक्फ या उसके वंशजों या उसके परिवार के किसी सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का भरण-पोषण और समर्थन,

(ख) वाकीफ या उसके परिवार के किसी सदस्य की पुण्यतिथि से जुड़े धार्मिक समारोहों का उत्सव या उसके किसी भी पूर्वजों;

(ग) निजी इमामबाड़ों, मकबरों और कब्रों का रखरखाव

गज, या

(घ) वाकीफ के रखरखाव और समर्थन या उसके ऋणों के भुगतान के लिए, जब वाकीफ एक हनफी मुसलमान है; और (ग) अनुसूची में उल्लिखित वक्फ।

बशर्ते कि यदि किसी वक्फ का मुतवल्ली जिसके लिए यह अधिनियम

गलत तरीके से बिक्री या बंधक लागू नहीं होता है, या अपने खिलाफ डिक्री के निष्पादन में बेचे जाने के लिए पीड़ित नहीं होता है, या अन्यथा वक्फ संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से को नष्ट कर देता है, केंद्रीय बोर्ड इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान को ऐसे वक्फ पर ऐसे समय के लिए लागू कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। स्पष्टीकरण-एक वक्फ जिसे मूल रूप से इस अधिनियम के संचालन से छूट दी गई है, बाद में किसी भी कारण से, इस तरह के संचालन के अधीन हो सकता है, उदाहरण के लिए, अधिक प्रतिशत के कारण

इसकी आय सार्वजनिक दान के लिए विलेख की शर्तों के तहत उपलब्ध हो रही है।

(जोर दिया गया)

46. 1936 के अधिनियम की धारा 3 (1) में 'वक्फ' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“ 3 (1) ‘ वक्फ का अर्थ है मुसलमान कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी संपत्ति का स्थायी समर्पण या अनुदान या

धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में उपयोग और, जहां वक्फ का कोई विलेख पता लगाने योग्य नहीं है, उसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ शामिल है, और वाकीफ का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो ऐसा समर्पण या अनुदान देता है।

47. 1936 के अधिनियम की धारा 38 (1) निम्नानुसार है:

बीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 38 (1) प्रत्येक वक्फ चाहे इस अधिनियम के अधीन हो या नहीं और क्या इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में बनाया गया होगा

संप्रदाय के केंद्रीय बोर्ड के कार्यालय में पंजीकृत जिसमें

वक्फ संबंधित है।

(जोर दिया गया)

48. इसमें कोई संदेह नहीं है कि फजलुल रब्बी प्रधान (ऊपर) में,

इस सवाल के संदर्भ में कि क्या वक्फ प्रभावित हुए थेपश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 और उस में,

विचाराधीन ए. क्यू. एफ. 'धर्मार्थ' शब्दों की परिभाषा के भीतर आता है।

न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ 'धार्मिक उद्देश्य' को निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 13. इन मामलों ने भारत और मुसलमान में आंदोलन को जन्म दिया

वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913 (1913 का 6) पारित किया गया था। उन्होंने घोषणा की कि

के माध्यम से संपत्ति का निपटान करने के लिए मुसलमानों के अधिकार उनके परिवारों, बच्चों और वंशजों के पक्ष में वक्फ। के लिए

विधिमान्य अधिनियम के उद्देश्यों के लिए "वक्फ" शब्द को परिभाषित किया गया था।

वक्फ शब्द का व्यापक अर्थ लेकिन केवल लेने के उद्देश्य से उन्हें अयोग्यता से बाहर निकालना जो अन्यथा मौजूद होता

और जिसे पहले से ही आधिकारिक रूप से अस्तित्व में होने के लिए कहा गया था।

14. इन दो अधिनियमों के पारित होने के बाद वक्फ, जिसमें

उद्देश्य बिना वाकीफों के परिवारों की उन्नति थी

सामान्य अर्थों में दान का ढोंग, वैध हो गया और

ऑपरेटिव। लेकिन वैलिडेटिंग एक्ट का इरादा देने का नहीं था

"दान" शब्द का एक नया अर्थ जो आम बोलचाल में है

एक ऐसा शब्द है जो किसी को आवश्यक रूप से देने को दर्शाता है

परिस्थितियों और कानून में सार्वजनिक भलाई के लिए देना। एक निजी उपहार

इस तरह के उपहारों को कभी भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नहीं माना गया
मुसलमान कानून के तहत भी। यह सैयद मोहिउद्दीन में शासित था।

यहाँ तक कि

अहमद बनाम। सोफिया खातून [44 सी. डब्ल्यू. एन. 974] कि न तो वक्फ

विधिमान्य अधिनियम 1913 और न ही शरीयत अधिनियम 1937 का प्रभाव था -

"धर्मार्थ" के अर्थ पर प्रिवी काउंसिल के फैसलों को निरस्त करना

उद्देश्य "जैसे". [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. इसमें कोई शक नहीं कि अदालत एक वक्फ-अलाल के मामले की सुनवाई कर रही थी।

ओलाड। निर्णय को अनिवार्य रूप से विचाराधीन अधिनियम में प्रदान की गई 'धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य' की परिभाषा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

50. वक्फिन प्रश्न दिनांकित 26.07.1934 है। 1936 का अधिनियम अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में बनाए गए वक्फों पर लागू होता है। हालाँकि, धारा 2 (2) घोषणा करती है कि यह अधिनियम कुछ वक्फों पर लागू नहीं होगा। इनमें एक वक्फ शामिल था जिसके तहत कुल आय का कम से कम 75 प्रतिशत, कुछ राशियों की कटौती के बाद, वक्फ या उसके वंशजों के लाभ के लिए देय था। हालाँकि, 1936 के अधिनियम की धारा 38 (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक वक्फ, चाहे वह अधिनियम के अधीन हो या नहीं और चाहे वह 1936 के अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया हो या नहीं, पंजीकृत किया जाएगा। इस आधार पर कार्यवाही करते हुए कि दिनांकित वक्फ 16.07.1934 वक्फ-अलाल-ओलाड था और जो धारा 2 (2) (i) के संदर्भ में, 1936 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं था, यह धारा 38 (1) को देखते हुए अनिवार्य रूप से पंजीकृत था। 1936 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी वक्फ को भी पंजीकृत माना जाएगा।

1960 के अधिनियम के तहत। यानी, हालाँकि 1936 का अधिनियम कुछ वक्फों पर लागू नहीं होता था, लेकिन जब धारा 38 के तहत पंजीकरण की बात आती है, तो यह था

प्रत्येक वक्फ के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है (i) चाहे वह अधिनियम के अधीन हो और ii) चाहे वह अधिनियम से पहले बनाया गया हो या नहीं। इस प्रकार, वक्फ दिनांक 1 का पंजीकरण वास्तव में 1936 के अधिनियम की धारा 38 के तहत अनिवार्य था।

51. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में कानून में ज्ञात कोई वक्फ नहीं था और विचाराधीन वक्फ ने केवल पूरी आय के वितरण पर विचार किया था।

वक्फ के वंशजों को लाभ। इस तथ्य के अलावा कि इस प्रश्न ने मुकदमे के पहले दौर में उच्च न्यायालय सहित दीवानी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह पाया गया कि शिया कानून के दृष्टिकोण से एक वैध वक्फ था और समेकन अधिकारियों ने यह भी पाया कि उप निदेशक तक एक वक्फ था, समेकन ने केवल समझौते के आधार पर मामले पर पुनर्विचार किया।

भाइयों के बीच, वक्फ की शर्तों में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित करने पर विचार किया गया था जैसा कि उत्तरदाता 2 और 4 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. आर. सिंह ने सही ढंग से बताया था। इस संबंध में, हम विलेख में इस शर्त को देखते हैं कि रु। 500 / - मुहर्रम के पवित्र महीने के मस्जिद और इमामबाड़ा, मजलिस अशरा में मुअज्ज़िन और रोशनी जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों पर खर्च किया जाएगा।

नो साबीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

वेगम और अन्य 2,3 को एक तर्क से निपटना पड़ा कि एक मामले में वक्फ-अलाल-औलाद, 1960 के अधिनियम की धारा 3 (11) में 'वक्फ' शब्द की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, क्या पूरी संपत्ति धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित थी, जैसा कि इसमें विचार किया गया है।

धारा 3 (11), 'वक्फ' शब्द को परिभाषित करती है या केवल सीमित सीमा तक, यानी आय की सीमा तक जो ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई थी।

हम इस संबंध में निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान दे सकते हैं:

" 5 बहुत सम्मान के साथ, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे लिए ऐसा प्रतीत होता है कि संपत्ति की सीमा आय के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती है। यह समर्पण है जो देखा जाना चाहिए, यदि पूरी संपत्ति दो उद्देश्यों के लिए समर्पित है, अर्थात्, धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए और धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए, तो पूरी संपत्ति दोनों उद्देश्यों के लिए समर्पित मानी जाएगी। जब तक यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि संपत्ति को धार्मिक, पवित्र और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किस हद तक समर्पित किया गया है, तब तक पूरी संपत्ति को समर्पित माना जाएगा।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील-उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि समर्पण की सीमा निर्धारित करने के लिए आय ही मानदंड है। लेकिन, हम पाते हैं कि यह वह आय नहीं है जिस पर वक्फ की परिभाषा में विचार किया गया है, बल्कि संपत्ति है। प्रासंगिक शब्द 'उस हद तक जिसके लिए संपत्ति समर्पित है' हैं। आय संपत्ति से उत्पन्न होती है और यह भिन्न हो सकती है। समय-समय पर। यह धार्मिक, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए निर्धारित राशि से अधिक या उससे कम हो सकती है। यह.

राशि के सापेक्ष संपत्ति का आवंटन करना या यह कहना भी संभव नहीं है कि यह राशि किसी विशेष हिस्से या संपत्ति के किसी विशेष अनुपात से आनी चाहिए।

23 आकाशवाणी 1977 सभी 18 [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस संपत्ति को। पूरी संपत्ति, जो वक्फ का विषय है, धार्मिक, धार्मिक या धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। परोपकारी। यदि पूरी संपत्ति, जो वक्फ का विषय है, खर्चों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वक्फ या समर्पण कुल संपत्ति में से कुछ अनिश्चित और अनिश्चित संपत्ति की सीमा तक है, जो वक्फ का विषय है। हमारी राय में, जब तक धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वक्फ-अलाल-औलाद की विषय-वस्तु संपत्ति से संपत्ति की सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, तब तक पूरी संपत्ति वक्फ अधिनियम के अर्थ के भीतर वक्फ की विषय-वस्तु होगी। सीमा निर्धारित करने का प्रश्न व्यावहारिक रूप से केवल उस मामले में उत्पन्न हो सकता है जिसमें कई संपत्तियां हैं और उनमें से कुछ को धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है और अन्य को वक्फ या उसके वंशजों के लाभ के लिए निर्धारित किया गया है। यह ऐसे मामले में भी उत्पन्न हो सकता है जहां किसी संपत्ति या संपत्ति के किसी हिस्से में हिस्सेदारी दोनों उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई हो। वर्तमान मामले में दोनों वक्फों में से कोई भी नहीं है।

ऐसी दिशा। पूरी संपत्ति को धार्मिक, पवित्र और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि जो संपत्ति धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की गई है, वह संपत्ति का पूरा विस्तार है। संपत्ति। इसलिए विलेखों के तहत पूरी संपत्तियों को वक्फ अधिनियम की धारा 3 (11) के अर्थ के भीतर वक्फ माना जाएगा।

53. हम सोचेंगे कि उपरोक्त दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है और आय की सीमा, जो इस उद्देश्य के लिए अलग रखी गई है, चाहे वह धार्मिक हो, पवित्र हो या धर्मार्थ, तथ्यों में, पूरी संपत्ति के समर्पण से विचलित नहीं हो सकती है।

54. एक अन्य विवाद यह है कि वक्फ संपत्ति का विशाल विस्तार

मूल वाकीफ के बेटों द्वारा अलग किया गया था और केवल लगभग 100 बीघा जो हमारे सामने अपीलों का विषय है। रह गए। हमारा विचार है कि तर्क बिंदु से परे है। यह तथ्य कि वक्फ की संपत्ति से इस तरह से निपटा गया है, जो अवैध है, या इस पर सवाल नहीं उठाया गया है, हमें या तो यह पता लगाने से विचलित नहीं कर सकता है कि एक वैध वक्फ था या जो संपत्ति वक्फ की बची हुई थी, उससे कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। उप निदेशक (समेकन) के समक्ष समझौता और आदेश साबीर अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

उसी के आधार पर 1960 के अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत हैं, इसलिए समेकित अधिकारी और निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश

वक्फ के बारे में पुनर्जीवित होगा।

55. दो सवाल बाकी हैं। पहला सवाल, जिस पर हमें विचार करना चाहिए, वह यह है कि क्या वक्फ का कोई लाभार्थी वक्फ की संपत्ति के संबंध में प्रतिकूल कब्जे की याचिका के बल पर सफल हो सकता है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि एक मुतवल्ली प्रतिकूल कब्जे से खिताब हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकता है। समान रूप से, एक ट्रस्टी और एक सह-मालिक इस संबंध में वर्जित हैं, यह नोट किया गया है। एक का लाभार्थी वक्फ, हालांकि, न तो ट्रस्टी होने के नाते और न ही वक्फ संपत्ति का सह-मालिक होने के नाते, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, भले ही वह वक्फ की संपत्ति हो।

56. वक्फ के लाभार्थी को वक्फ के लिए अजनबी नहीं बताया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक लाभार्थी को उसकी स्थिति में मुतवल्ली के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुतवल्ली वक्फ का प्रबंधक है। वक्फ की संपत्ति, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए, कानून सर्वशक्तिमान में निहित है। मुतवल्ली केवल प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। सीमा अधिनियम की धारा 10 के प्रयोजनों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे न्यासी के रूप में माना जाता है। प्रतिकूल अधिकार की याचिका के लिए निस्संदेह अपेक्षित इरादे की आवश्यकता होती है, अर्थात्, संभव है। यह आवश्यक अवधि के लिए वास्तविक कब्जे के अलावा है। क्या लाभार्थी वक्फ संपत्ति के लिए एक प्रत्ययी क्षमता रखता है, जो उसे प्रतिकूल के दावे को आगे बढ़ाने से रोकता है

अधिकार? इस संदर्भ में 'प्रत्ययी क्षमता' शब्द क्या व्यक्त करते हैं? एक लाभार्थी वक्फ विलेख के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। क्या वक्फ संपत्ति के संबंध में उसका कोई दायित्व है? क्या दूसरे शब्दों में कोई ऐसा कर्तव्य है जिसे उसे इस तथ्य के आधार पर निभाना चाहिए कि वह वक्फ के तहत एक लाभार्थी है? क्या प्रतिकूल अधिकार का दावा, प्रतिकूल अधिकार का गठन करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है जो लाभार्थी की स्थिति के साथ अपरिवर्तनीय और असंगत है? प्रतिकूल कब्जे के मामले में, चूंकि एक आवश्यकता यह है कि कब्जा वास्तविक मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण होना चाहिए और चूंकि वास्तविक मालिक सर्वशक्तिमान है, इसलिए आवश्यकता यह होगी कि ऐसे व्यक्ति के पास आवश्यक अधिकार होने चाहिए।

भगवान की उपाधि के विपरीत धारण करने के लिए शत्रुता। एक सह-मालिक के मामले में, जबकि केवल अपने आप में स्वामित्व का दावा करना शायद ही पर्याप्त हो क्योंकि एक सह-मालिक के कब्जे को सभी सह-मालिकों की ओर से कब्जे में लिया जाता है, निष्कासन का मामला सफलतापूर्वक स्थापित होने से अधिकार प्राप्त होगा

सफल होने के लिए सह-मालिक।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

57. हम "मुस्लिम कानून के सिद्धांतों" (22 वां संस्करण) पर मुल्ला के निम्नलिखित कथन को देख सकते हैं:

" 207. बेचने या गिरवी रखने की मुतवल्ली की शक्ति। मुतवल्ली के पास अदालत की अनुमति के बिना वक्फ संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से को गिरवी रखने, बेचने या विनिमय करने की कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि वह वक्फ के विलेख द्वारा ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से सशक्त न हो।

58. इसके बाद विद्वान लेखक अधिनियम की धारा 51 (1) का उल्लेख करता है जिसके तहत कोई संदेह नहीं है कि पूर्व प्राप्त करने के बाद बिक्री की जा सकती है।

बोर्ड की मंजूरी। संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया परिवर्तन

2013 के अधिनियम की धारा 51 में उप-धारा (1 ए) को शामिल करके, जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री को शून्य घोषित किया गया है, भी देखा गया है। बिक्री के खिलाफ प्रतिबंध जब तक कि इसे वक्फ विलेख द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक "अनधिकृत अलगाव और सीमा" शीर्षक के तहत निपटा जाता है और यह निम्नानुसार है:

" मुतवल्ली के हाथों में वक्फ संपत्ति का पालन करने और ऐसी संपत्ति के अनधिकृत हस्तांतरण को अलग रखने और कब्जे की वसूली करने के लिए एक मुकदमे के लिए सीमा की अवधि के संबंध में कानून

अंतरिती से, 1929 के अधिनियम 1 द्वारा संशोधित और परिवर्तित किया गया था। संशोधनों में एस में पैरा 2 जोड़ा गया है। 10 मूल अधिनियम (सीमा अधिनियम, 1908) और नई वस्तुओं को शामिल करने का, जो कलाएँ हैं। 48 बी, 134 ए, 134 बी और 134 डिग्री सेल्सियस "।

59. हम पहले ही सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 134 बी के उद्देश्य और उत्तराधिकारी में लागू गए परिवर्तन को देख चुके हैं।

प्रावधान, अर्थात्, सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 96।

60. अनीसुर रहमान और अन्य बनाम। शेख अबुल हयात 2 4, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के पास इस मामले से निपटने का अवसर था

जिस प्रश्न का हम सामना कर रहे हैं। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया:

" 7. हिंदू लॉ ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट पर मुखर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक, दूसरे संस्करण में, पृष्ठ 274 पर, उक्त कलकत्ता निर्णय का उल्लेख किया गया था और इसे आगे पृष्ठ पर इंगित किया गया था।

282 कि अनधिकृत अलगाव के मामले में सीमा किसी भी संपत्ति के संबंध में कब्जा निहित होते ही शुरू हो जाएगी। को।

282 पर उनके अपने शब्दों का उद्धरण दें:

पृष्ठ

24 एयर 1965 पटना 390 बीर अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

" इन मामलों से जो सही सिद्धांत निकाला जा सकता है वह यह है कि जैसे ही वह संपत्ति पर किसी भी अधिकार के बिना होगा, विदेशी का कब्जा प्रतिकूल हो जाएगा। यदि हस्तांतरण शुरू से ही शून्य है, तो हस्तांतरणकर्ता का कब्जा हस्तांतरण की तारीख से प्रतिकूल है। यदि, दूसरी ओर, यह शून्य नहीं है, लेकिन शून्य है

केवल उत्तराधिकारी प्रबंधक के कहने पर, कब्जा तब तक प्रतिकूल नहीं हो सकता जब तक कि स्थानांतरण प्रबंधक का कार्यालय बंद नहीं हो जाता।

9. एक स्थानांतरण जो शुरुआत से ही शून्य है, कानून की नजर में कोई स्थानांतरण नहीं है और इसलिए यह अनुच्छेद 134 बी के दायरे में नहीं आएगा। इसके अलावा, वह अनुच्छेद एक प्रबंधक द्वारा किए गए स्थानांतरण को संदर्भित करता है

एक दान। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति को हस्तांतरित करता है तो उसे अपना मानता है।

निजी संपत्ति का मालिक है, यह मानना मुश्किल है कि केवल इसलिए कि वह उस तारीख को बंदोबस्ती का प्रबंधक होता है हस्तांतरण और संपत्ति इस तरह के बंदोबस्ती का अधिकार है

हस्तांतरण उस अनुच्छेद के दायरे में आना चाहिए। श्री हुसैन

क्योंकि अपीलार्थी ए. आई. आर. 1946 के बाद किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं कर सके।

473 इस प्रभाव के लिए अपने चरम विवाद के समर्थन में कि उस निर्णय में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार 1929 के संशोधन के लागू होने के बाद किए गए अमान्य हस्तांतरण के संबंध में उनका कोई आवेदन नहीं है। दूसरी ओर, उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने गोविंदा जीव ठाकुर बनाम. सुरेंद्र जेना, आकाशवाणी 1961

उड़ीसा 102 ने उस निर्णय के सिद्धांत को लागू किया और कहा कि

इस तरह के मामले में हस्तांतरणकर्ता केवल एक अतिचारक है और उसका खिताब बारह साल के प्रतिकूल कब्जे से परिपूर्ण हो जाएगा। सम्मान के साथ मैं इस दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए इच्छुक हूं। मद्रास का भी एक निर्णय है। वी. राजाराम बनाम। रामानुजम अयंगर, ए. आई. आर. 1963 मद्रास

पैराग्राफ 4 और 5 एक ही प्रभाव के लिए।

61. इसलिए, जो सिद्धांत उभरता है, वह यह है। अनुच्छेद 96 के तहत आने के लिए, एक प्रबंधक द्वारा स्थानांतरण होना चाहिए जिसमें एक वक्फ का मुतवल्ली शामिल होगा। यह मूल्यवान उपहास के लिए होना चाहिए। ताकि एक स्थानांतरण हो, यह अभी भी पैदा नहीं होना चाहिए। यह.

घ एक शून्य लेन-देन नहीं होगा। यही कारण है कि एक शून्य [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेन-देन हस्तांतरण के बराबर नहीं होगा। एक अनधिकृत अलगाव जैसा कि मुल्ला (उपरोक्त) में समझा गया है, जिसका हमने उल्लेख किया है। , एक स्थानांतरण, जो एक मुतवल्ली द्वारा किया गया था, जिसके लिए कोई अधिकार नहीं था

वक्फ विलेख, एक हस्तांतरण का गठन करेगा जिस पर अनुच्छेद 134 बी और अनुच्छेद 96 लागू होता। वक्फ से संबंधित कानूनों के आगमन के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1960 का अधिनियम शामिल था, मुतवल्ली संबंधित बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के लिए बाध्य था। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना 1960 के अधिनियम के तहत स्थानांतरण किया जाता है, स्थानांतरण अमान्य होगा। यही कारण है कि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता एक वैधानिक आदेश है।

एक निश्चित और उदात्त उद्देश्य और उल्लंघन के साथ कल्पना की गई

जिसके परिणामस्वरूप केवल एक शून्य लेनदेन हो सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसी बिक्री को मान्य करने में सक्षम बनाता हो। वास्तव में, उत्तरदाता 2 और 4 का रुख यह है कि स्थानांतरण अमान्य थे। इसलिए, अधिकारियों ने इस आधार पर भी कार्रवाई की है कि लेन-देन अमान्य था और इसलिए हम उक्त आधार पर आगे बढ़ सकते हैं।

62. इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि 1974 में निष्पादित बिक्री एक शून्य लेनदेन था, हम उनके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। चिंतामणि साहू (एल. आर. द्वारा मृत) (ऊपर) और अनीसुर रहमान (ऊपर), जिनका हमने उल्लेख किया है और माना है कि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 96 को अमान्य लेनदेन के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। उक्त आधार पर चल रहे विवादित आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

63. हमारा विचार है कि इसके खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है।

प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण का दावा करने वाले वक्फ का लाभार्थी। वक्फ अधिनियम, 1955 की धारा 2 (के) इस प्रकार है:

" 2 (के) "वक्फ में रुचि रखने वाले व्यक्ति का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो

से कोई भी आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार है

वक्फ और इसमें शामिल हैं

((i)

कोई भी व्यक्ति जिसे प्रार्थना करने या करने का अधिकार है

किसी मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह, खानकाह, पीरखाना और कर्बला, मकबरा, कब्रिस्तान या वक्फ से जुड़ी किसी अन्य धार्मिक संस्था में कोई धार्मिक संस्कार या वक्फ के तहत किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्था में भाग लेना।

((ख)

वक्फ और वक्फ के किसी भी वंशज और

मुतवल्ली; साबीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

64. जबकि वह एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे धारा 2 (के) के अर्थ के भीतर एक वक्फ में "रुचि" के रूप में माना जा सकता है, दोनों तथ्यों के कारण। कि वह आर्थिक या अन्य लाभ का प्राप्तकर्ता है और वह वाकीफ का वंशज भी हो सकता है, यह उसे न्यासी के रूप में वर्णित करने से बहुत दूर है। वक्फ विलेख के संदर्भ में लाभार्थी को लाभ मिल सकता है। उसे इस संबंध में अधिकार दिए जा सकते हैं।

65. क्या यह कहा जा सकता है कि वक्फ का लाभार्थी न्यासी है या

कि एक प्रत्ययी संबंध है और इसलिए, वह प्रतिकूल कब्जे से वक्फ की संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है? 'प्रत्ययी' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए 'प्रत्ययी संबंध' के मामले में भी ऐसा ही है। वास्तव में, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 88,

अन्य रूप से, यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो एक प्रत्ययी चरित्र में खड़ा है और दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है, इस तरह के चरित्र का उपयोग करके, प्राप्त नहीं कर सकता है एक लाभ और उस व्यक्ति को लाभ देने का विरोध करें, जिसके हित की वह रक्षा करने के लिए बाध्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और एक अन्य V. आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य 2, हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में, यह सवाल उठा कि क्या एक जाँच निकाय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ई) के अर्थ के भीतर एक प्रत्ययी संबंध में मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को रखता है। निर्णय के दौरान, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 38. "प्रत्ययी" और "प्रत्ययी संबंध" शब्द विभिन्न क्षमताओं और संबंधों को संदर्भित करते हैं, जिसमें एक सामान्य कर्तव्य शामिल है।

या दायित्व।

38.1. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (7 वां संस्करण, पृ. 640) परिभाषित करता है

" न्यासी संबंध "इस प्रकार:

" विश्वास संबंधी संबंध। एक रिश्ता जिसमें

व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह संबंध के दायरे में आने वाले मामलों पर दूसरे के लाभ के लिए कार्य करे। न्यासी-लाभार्थी, अभिभावक-वार्ड, अभिकर्ता-प्रधान और वकील-ग्राहक जैसे न्यासी संबंधों को देखभाल के उच्चतम कर्तव्य की आवश्यकता होती है। न्यासी

संबंध आमतौर पर चार स्थितियों में से एक में उत्पन्न होते हैं: (1) जब एक व्यक्ति दूसरे की वफादार अखंडता में विश्वास रखता है, जो परिणामस्वरूप पहले पर श्रेष्ठता या प्रभाव प्राप्त करता है, (2) जब एक व्यक्ति दूसरे पर नियंत्रण और जिम्मेदारी ग्रहण करता है, (3) जब

एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह दूसरे के लिए कार्य करे या उसे सलाह दे।

25 (2011) 8 एससीसी 497 [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंध के दायरे में आने वाले मामले, या (4) जब एक विशिष्ट संबंध है जिसे पारंपरिक रूप से मान्यता दी गई है

प्रत्ययी कर्तव्यों को शामिल करते हुए, जैसे कि एक वकील और एक मुवक्किल या एक स्टॉक ब्रोकर और एक ग्राहक "।

XXX

XXX

XXX

39. "प्रत्ययी" शब्द एक कर्तव्य रखने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है।

दूसरे के लाभ के लिए कार्य करना, सद्भावना और स्पष्टता दिखाना,

जहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति विश्वास और विशेष विश्वास रखता है कर्तव्य का वहन या निर्वहन करने वाला व्यक्ति। "न्यासी" शब्द

"संबंध" का उपयोग किसी स्थिति या लेनदेन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहाँ

एक व्यक्ति (लाभार्थी) दूसरे पर पूरा विश्वास रखता है।

व्यक्ति (प्रत्ययी) अपने मामलों, व्यवसाय या लेन-देन के संबंध में।

लाभार्थियों से संबंधित चीजें। यदि लाभार्थी न्यासी को कुछ भी सौंपने के लिए, चीज़ को विश्वास में रखने के लिए या

सौंपे गए व्यक्ति के संबंध में या उसके संदर्भ में कुछ कार्यों को निष्पादित करना।

बात यह है कि न्यासी को विश्वास में कार्य करना पड़ता है और उम्मीद की जाती है कि वह ऐसा नहीं करेगा किसी तीसरे पक्ष को चीज़ या जानकारी का खुलासा करें।

40. कुछ ऐसे संबंध भी हैं जहाँ दोनों

पक्षों को एक प्रत्ययी क्षमता में कार्य करना होगा जो दूसरे के साथ व्यवहार करता है

भागीदार और एक नियोक्ता बनाम कर्मचारी। एक कर्मचारी जो व्यवसाय या व्यापार रहस्य या गोपनीय के कब्जे में आता है

अपने कार्यकाल के दौरान नियोक्ता से संबंधित जानकारी रोजगार, एक प्रत्ययी के रूप में कार्य करने की उम्मीद है और खुलासा नहीं कर सकता है

दूसरों के लिए। इसी तरह, यदि नियोक्ता या अधिकारी के अनुरोध पर

वरिष्ठ अधिकारी या किसी विभाग का प्रमुख, एक कर्मचारी अपना काम करता है।

व्यक्तिगत विवरण और जानकारी, जिसे विश्वास में रखा जाना है,

नियोक्ता, आधिकारिक वरिष्ठ या विभागीय प्रमुख अपेक्षित है।

ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को न्यासी के रूप में विश्वास में रखना,

उपयोग या खुलासा केवल तभी किया जाए जब कर्मचारी का आचरण या
लिए प्रतिकूल पाए जाते हैं।

अधिनियम नियोक्ता के

66. इसलिए, एक न्यासी को एक ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है जो बन जाता है

दूसरे के हितों की रक्षा करने के कर्तव्य के साथ। न्यासी

आनशिप की नींव एक दूसरे पर विश्वास रखने पर टिकी होती है।

साबीर अली खान बनाम। सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

सर्वशक्तिमान में निहित, एक चिंता होनी चाहिए और निस्संदेह, एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस तरह से कार्य करे कि वक्फ के उद्देश्य को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन एक लाभार्थी एक न्यासी की तरह नहीं होता है, जो न्यासी के रूप में अपने चरित्र पर कब्जा कर लेता है, न्यासी के रूप में अपने चरित्र को त्यागने और अतिक्रमण करने वाले या दावा करने वाले व्यक्ति के वस्त्र पहनने के प्रतिबंध के तहत आता है। शत्रुतापूर्ण शीर्षक। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 14 इस प्रकार है:

" 14. न्यासी को लाभार्थी के प्रतिकूल स्वामित्व स्थापित नहीं करना चाहिए-न्यासी को अपने लिए या किसी अन्य संगठन के लिए या लाभार्थी के हित के प्रतिकूल न्यास संपत्ति के किसी भी स्वामित्व की सहायता नहीं करनी चाहिए।

67. ऐसा नहीं है कि बिक्री से पहले किसी भी क्षमता में संपत्ति पर लाभार्थी का कब्जा था।

एक समझौते की ताकत और उप निदेशक, समेकन का आदेश, जिसके तहत, वह कथित रूप से एक के रूप में कार्य करता है अपने आप में एक-तीसरा अधिकार। हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अनुच्छेद 96 की प्रयोज्यता के लिए बहुत कम मायने रखता है कि हस्तांतरणकर्ता ने वक्फ संपत्ति को अपनी संपत्ति होने का दावा करते हुए स्थानांतरित करने का इरादा किया था, जो इस अदालत ने श्रीनिवास (उपरोक्त) में निर्धारित किया है। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जहां शून्यता इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि जो वक्फ संपत्ति पाई गई है, उसे वैधानिक जनादेश के विपरीत अलग किया गया है। हमने 1960 के अधिनियम की धारा 69 और उसके प्रभाव पर भी ध्यान दिया है।

69. यह तर्क कि अधिनियम की धारा 107 सहायता करेगी

सीमा की सीमा को पार करने में अपीलकर्ता हमें आकर्षित नहीं करता है। अधिनियम की धारा 107, निस्संदेह, घोषणा करती है कि सीमा अधिनियम, 1963 में कुछ भी किसी भी वक्फ में शामिल अचल संपत्ति के कब्जे या ऐसी संपत्ति में किसी भी हित के कब्जे के लिए किसी भी मुकदमे पर लागू नहीं होगा।

70. यह अधिनियम 01.01.1996 पर लागू हुआ। पहली बिक्री 14.10.1960 पर की गई थी। दूसरी बिक्री 26.09.1974 पर की गई थी।

जहाँ तक पहली बिक्री का संबंध है, हम पहले ही पा चुके हैं कि अनुच्छेद 96 को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि हस्तांतरण मुतवल्ली द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं था। अनुच्छेद 65 को लागू करने के लिए दरवाजे खुले थे। जहाँ तक दूसरी बिक्री का संबंध है जो [2023] 6 एस. सी. आर. से प्रभावित हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 1974 में हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद 96 लागू नहीं था, स्वीकृति के लिए एकमात्र अन्य प्रतिस्पर्धी अनुच्छेद, अनुच्छेद 65 प्रतीत होता है। अनुच्छेद 65 को लागू करना और प्रतिकूल अधिकार के रूप में हस्तांतरण की तारीख से, बारह साल की समाप्ति पर, यानी 1986 में सीमा अधिनियम की धारा 27 को लागू करना, धारा 65 के अर्थ के भीतर जो भी शीर्षक बचा होगा, वह समाप्त हो जाएगा। अधिनियम को केवल 01.01.1996 से लागू किया गया था। हम धारा 107 के उद्देश्य को यह नहीं समझ सकते कि यह धारा को पुनर्जीवित करेगी।

समाप्त शीर्षक के रूप में कानून के तहत दूसरी बिक्री की तारीख से समय के चलने के रास्ते में कुछ भी नहीं था।

71. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकदमे की तारीख को सीमा का कानून लागू होता है (सी. बीपथुम्मा और अन्य बनाम देवे। वेलासरी

शंकरनारायण कदम्बोलिथाय और अन्य 26)। 1997 के रूप में लेना जिस तारीख को मुकदमा दायर किया जाता है और उस अधिनियम को लागू किया जाता है, जो वादी को सीमा कानून की अवहेलना करने में सक्षम बनाता है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि

जो पहले के कानून के तहत बुझ गया था वह पुनर्जीवित होगा। इस संबंध में, हम टी. कलियमूर्ति (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देते हैं:

" 40. इस पृष्ठभूमि में, आइए अब देखें कि क्या इस खंड का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कोई कानून नहीं होगा

अपनी भाषा तक एक पूर्वव्यापी संचालन करने के लिए समझा जाए

ऐसा है जिसके लिए इस तरह के निष्कर्ष की आवश्यकता होगी। इस नियम का अपवाद प्रक्रिया से संबंधित अधिनियम हैं। इसका अर्थ यह होगा कि सीमा का कानून, एक प्रक्रियात्मक कानून होने के नाते, इस अर्थ में पूर्वव्यापी है कि यह अधिनियम के समय लंबित कार्यवाही और उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही पर भी लागू होगा, भले ही कार्रवाई का कारण नए प्रावधानों के लागू होने से पहले उत्पन्न हुआ हो। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। जहां नया प्रावधान लागू होने से पहले लागू सीमा कानून के तहत मुकदमे का अधिकार वर्जित है और एक निहित अधिकार दूसरे को प्राप्त हो गया है, तो नया प्रावधान वर्जित अधिकार को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है या अर्जित निहित अधिकार को छीन नहीं सकता है। " "

72. एक तर्क लिया जाता है कि न्यायालय एक मुकदमे पर विचार नहीं कर रहा है और मामला अधिनियम की धारा 52 के तहत एक कार्यवाही से उत्पन्न होता है। यह.

यह तर्क दिया जाता है कि धारा 52 के संबंध में मुकदमे के लिए सीमा का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। हमने देखा है कि उच्च न्यायालय में बहस अनिवार्य रूप से

26 एयर 1965 एससी 241 साबीर अली खान बनाम।

सैयद मोहम्मद। अहमद अली खान और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

इस सवाल के इर्द-गिर्द केंद्रित कि क्या अनुच्छेद 96 लागू होगा और इसे लागू करेगा, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित अनुच्छेद 65 के प्रभाव के बारे में जान सकता है। हमने पाया है कि अनुच्छेद 96 का कोई उपयोग नहीं है। अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही के संबंध में भी, चाहे वह धारा 52 हो, यदि कार्रवाई की तारीख को, सीमा अधिनियम की धारा 27 के आधार पर संपत्ति में स्वामित्व उस व्यक्ति के पास निहित था जो अधिकार अर्जित किया गया था, तो उस अधिकार की उपेक्षा करने की अनुमति नहीं हो सकती है। टी. कलियमूर्ति (ऊपर) में निर्णय तथ्यों में लागू होगा और कार्रवाई वर्जित है।

73. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि अपीलों को बिना योग्यता के पाया जाना चाहिए और खारिज कर दिया जाएगा। पार्टियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है

संबंधित लागतें।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन

(तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)